राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण गुरुवार 24 सितंबर 2026 वर्ष-9,अंक-233 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप- राउत ने मुख्य चुनाव आयुक्त और शाह पर साधा निशाना

पीएम मोदी तुरंत केंद्रीय मंत्री शाह को पद से हटाएं

नई दिल्ली ।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में कथित हेरफेर का हवाला देकर दोनों को तुरंत उनके पदों से हटाने की मांग की। नई दिल्ली में प्रेसवार्ता को संबोधित कर शिवसेना यूबीटी नेता राउत ने अखबार की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें दो अन्य चुनाव आयुक्तों की आपत्ति का जिक्र था। राउत के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने बीते 10 महीनों में एसआईआर (समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स) और फॉर्म 6 में बदलावों को लेकर 14 बार अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार ने उन्हें नजरअंदाज किया। शिवसेना (यूबीटी) नेता राउत ने दावा किया कि इन आपत्तियों को कैबिनेट सचिव को बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार की वजह से भाजपा बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव जीत रही है, और यह सब केंद्रीय मंत्री शाह के इशारे पर हो रहा है। राउत ने ज्ञानेश कुमार को तुरंत निलंबित करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव एक मजाक बन गए हैं, और चुनाव आयोग अब गृह मंत्रालय के अधीन आता है। शिवसेना यूबीटी नेता राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमित शाह को कैबिनेट से हटाने का आह्वान किया, और अगर ऐसा नहीं होता है, तब उन्होंने राष्ट्रपति से कुमार को हटाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्रपति भी कार्रवाई नहीं करती हैं, तब सेना प्रमुख को हुक्मशाहों से देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। राउत ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत पूरे देश में 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को वोटों की चोरी नहीं, बल्कि वोटों की डकैती करार दिया, जिसे ईसीआई नेट नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से सरकार के इशारे पर अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया। राउत ने दावा किया कि इस सॉफ्टवेयर ने मनमाने ढंग से मतदाताओं के नाम हटाए हैं और बिना किसी गजट नोटिफिकेशन के सीईसी ने फॉर्म 6 में बदलाव किए हैं, जिससे मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार निजी कंपनियों को सौंप दिया गया है।

उभरते शहरों की नई तस्वीर- भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर भी वैश्विक सूची में

नई दिल्ली ।

भारत के शहर अब केवल देश की अर्थव्यवस्था के केंद्र नहीं रह गए हैं. वैश्विक आर्थिक बदलाव की नई कहानी भी लिख रहे हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की रिपोर्ट में दुनिया के 57 उभरते शहरों में भारत के 46 शहर शामिल हैं। खास बात यह है, मध्यप्रदेश के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर भी इस सूची में शामिल हैं। यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है, उभरते शहरों की पहचान केवल आबादी या क्षेत्रफल से नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक संभावनाओं, मानव संसाधन, व्यापार, बुनियादी ढांचे और भविष्य में विकास की क्षमता से होती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों में तकनीकी क्षेत्र, डिजिटल सेवाओं, बिजनेस सर्विसेज और नए आर्थिक अवसरों के विस्तार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।

मध्यप्रदेश के तीनों शहरों की अपनी अलग पहचान है। भोपाल प्रशासनिक राजधानी होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी और सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ग्वालियर ऐतिहासिक पहचान के साथ शिक्षा, पर्यटन और क्षेत्रीय कारोबार का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। वहीं जबलपुर रक्षा प्रतिष्ठानों, शिक्षा, न्यायिक गतिविधियों, स्वास्थ्य सेवाओं और आसपास के बड़े ग्रामीण बाजार के कारण मध्यप्रदेश के प्रमुख क्षेत्रीय केंद्रों में शामिल है। इन शहरों का वैश्विक सूची में पहुंचना अवसर के साथ चुनौती भी है। यदि बेहतर सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी, आधुनिक शहरी सुविधाएं, रोजगार, निवेश और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति दी जाए,तो यह शहर आने वाले वर्षों में प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदल सकते हैं।

पलामू- करम पर्व के दौरान बड़ा हादसा, नदी में डूबने से 5 की मौत

पलामू ।

झारखंड के पलामू जिले में आदिवासी पर्व करम के दौरान बड़ा हादसा हुआ।

बुधवार को कोयल नदी में करम डाल के विसर्जन के दौरान तीन नाबालिगों सहित पांच लोग डूब गए। यह दुखद घटना बोकया गांव में हुई। सरहुल के बाद झारखंड के प्रमुख आदिवासी पर्वों में से एक करम का समापन मंगलवार को हुआ था। इस पर्व में स्थापित की गई करम वृक्ष की डाल का विसर्जन किया जाता है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि विसर्जन के दौरान आठ वर्षीय हेमंत कुमार सिंह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के प्रयास में चार अन्य लोग भी नदी में कूदे और दुर्भाग्यवश सभी पांचों डूब गए।

पीएम मोदी के साथ कैबिनेट मंत्रियों का दो दिवसीय चिंतन शिविर

बैठक में कामकाज की समीक्षा, अगले चरण की प्राथमिकताओं पर चर्चा की उम्मीद

नई दिल्ली।

पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार 23 सितंबर से केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के साथ दो दिन का चिंतन शिविर करेंगे। यह बैठक नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में होगी और 24 सितंबर तक चलेगी। इसमें सरकार के कामकाज की समीक्षा, आगे की राह पर चर्चा और शासन के अगले चरण के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं की पहचान किए जाने की उम्मीद है। पहले की कुछ बैठकों के उलट इस बार के सत्र में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होंगे।

इस दो दिवसीय बैठक का समय काफी अहम माना जा रहा है। यह बैठक पीएम मोदी द्वारा अपने कार्यालय में राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के साथ की गई अलग-अलग बैठकों के बाद हो रही है। बैठकों का यह क्रम मंत्रिपरिषद के विभिन्न स्तरों को शामिल करते हुए एक सुनियोजित प्रक्रिया की ओर इशारा करता है, जिसमें अब कैबिनेट मंत्रियों के लिए उनकी अपनी समर्पित बैठक तय की गई है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक चिंतन शिविर पहले से चल रहे कामों का जायजा लेने, सरकार के अगले कदमों की योजना बनाने और विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़े आगे के सुधारों और प्राथमिकताओं की पहचान करने पर केंद्रित होगा।

चर्चाओं में सरकारी नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन की गति, सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी, मंत्रालयों के बीच समन्वय और शासन में सुधार के तरीकों पर चर्चा होने की उम्मीद है, ताकि यह तय किया जा सके कि सरकारी पहल जमीनी स्तर पर नतीजों में बदलें।

दो दिवसीय विचार-विमर्श कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रालयों में प्रगति का आकलन करने, अधिक समन्वय की जरुरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा, जो आने वाले समय में सरकार के काम को आकार दे सकती हैं। सेवा तीर्थ में यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब नया सरकारी परिसर पीएमओ और केंद्र सरकार के कामकाज में बड़ी भूमिका निभा रहा है।

चुनाव आयोग में मतभेद पर कांग्रेस के सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

दो चुनाव आयुक्तों की कथित 14 आपत्तियों को लेकर कांग्रेस ने पत्राचार सार्वजनिक करने और संसद में मुद्दा उठाने की बात कही

नई दिल्ली ।

निर्वाचन आयोग के भीतर चुनाव आयुक्तों के बीच कथित मतभेद को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में लिए गए कुछ फैसलों पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा आपत्ति जताए जाने को लेकर आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच हुए पत्राचार को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को संसद में भी उठाने की बात कही। बताया गया है कि पिछले 10 महीनों में दोनों चुनाव आयुक्तों ने कम से कम 14 बार कुछ फैसलों और आदेशों पर आपत्ति दर्ज कराई। ये मामले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने, नाम बहाल करने से जुड़े आदेशों के खिलाफ अपील तथा मतदाता डेटा की सुरक्षा और डिजिटल सिस्टम से संबंधित बताए गए हैं।

नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर भी आपत्ति सामने आने की बात कही गई है। इसमें एसआईआर से जुड़ा एक सवाल जोड़े जाने का उल्लेख है, जिसमें आवेदक से उसके या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में होने के बारे में जानकारी मांगी गई थी। विवेक जोशी ने इस बदलाव पर आपत्ति जताते हुए नियमों में संशोधन की आवश्यकता बताई थी। सुखबीर सिंह संधू ने भी इस पर सहमति जताई थी। मतदाता सूची के

डिजिटल डेटाबेस तक अधिकारियों की पहुंच को लेकर भी सवाल उठाए गए। विवेक जोशी ने डेटाबेस के केंद्रीकरण और उसमें बदलाव की अनुमति को लेकर ऑडिट की जरूरत बताई थी। बाद में सुखबीर सिंह संधू ने भी ईआरओनेट पोर्टल तक राज्य स्तर के अधिकारियों की पहुंच से जुड़ी चिंताओं का उल्लेख किया। दोनों आयुक्तों द्वारा इस संबंध में अलग-अलग पत्र लिखे जाने की बात सामने आई है।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और बहाल करने से जुड़े मामलों में अपील को लेकर भी आपत्ति का उल्लेख है। वहीं गोवा में 97 मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं हो पाने का मामला भी सामने आया, जबकि अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें सूची में शामिल करने योग्य माना था। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग में तीन सदस्य होते हैं और यदि दो चुनाव आयुक्त किसी फैसले पर आपत्ति जता रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि संबंधित फैसला किस प्रक्रिया के तहत लिया गया।

बसपा का परिवारवाद पर दांव- मायावती ने भतीजे ईशान आनंद को बनाया राष्ट्रीय संयोजक

लखनऊ।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने परिवारवाद के आरोपों के बीच बड़ा राजनीतिक दांव खेलकर लखनऊ में अपने भतीजे ईशान आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है। यह घोषणा पार्टी की राष्ट्रीय बैठक में की गई, जहाँ बसपा ने आगामी विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में अपने दम पर मैदान में उतरने का फैसला कर संगठन और चुनावी तैयारियों को तेज करने का ऐलान किया। राष्ट्रीय बैठक को संबोधित कर मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं से चुनावी जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने का आह्वान किया, विशेषकर उत्तरप्रदेश में पांचवीं बार सरकार बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने परिवारवाद के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बसपा हमेशा इससे अलग रही है और पार्टी संस्थापक कांशीराम का सिद्धांत था कि पूरा बहुजन समाज ही उनका परिवार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिश्तेदार संगठन में काम कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी व्यक्तिगत पारिवारिक हित के आधार पर नहीं होनी चाहिए। बसपा प्रमुख ने भाजपा सरकार पर निशाना साधकर कहा कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन और भ्रष्टाचार से जनता परेशान है, और आम लोगों के लिए अच्छे दिन की उम्मीद निराशा में बदल गई है।

राम मंदिर दान चोरी केस में 7000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल

- चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम शामिल नहीं

अयोध्या।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर आठों आरोपियों के खिलाफ एंटी करप्शन कोर्ट में 7 हजार पन्नों से अधिक की विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। विवेचक बुधवार सुबह बड़े-बड़े बक्सों में चार्जशीट लेकर कोर्ट पहुंचे, जिसमें आरोप पत्र के साथ-साथ बैंक स्टेटमेंट और बैंक की जमा पर्चियां भी मौजूद थीं। इस चार्जशीट में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम न होने पर मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने गहरी नाराजगी और असंतोष जताया है।

दाखिल की गई इस चार्जशीट में कुल 173 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और इसमें 105 बार चोरी होने का जिक्र किया गया है। इसके अलावा, रिकॉर्ड की गई जांच में 803 चीजों का रिकॉर्ड पूरी तरह सही पाया गया है, जबकि 86 कीमती चीजों की रसीद नहीं मिल सकी है। पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से कार, गहने और 79.85 लाख रुपये नकद बरामदगी का भी चार्जशीट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को जानकारी दी थी कि एसआईटी इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करेगी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस. के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने मीडिया और सोशल मीडिया पर मूल्यवान चढ़ावे से संबंधित लगाए गए सभी आरोपों का गहन सत्यापन किया था। एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मंदिर के तीर्थयात्री सुविधा केंद्र के गिनती

कक्ष के सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ कि गिनती प्रक्रिया में शामिल कुछ लोगों की मिलीभगत से कक्ष से नकदी को अनधिकृत रूप से निकालने या छिपाने के 105 मामले सामने आए थे।

चार्जशीट और एसआईटी की रिपोर्ट में कुल आठ आरोपियों की पहचान की गई है, तथा उनके बैंक खातों में जमा उस रकम का पूरा ब्यौरा दिया गया है जिसका कोई स्पष्ट स्रोत नहीं मिल सका है। इसके साथ ही, उन सभी चल और अचल संपत्तियों की जानकारी भी सार्वजनिक की गई है जिनमें चोरी का अवैध पैसा लगाया गया था। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और अधिवक्ताओं द्वारा नाम शामिल न किए जाने पर लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

मर्सिडीज वर्कशॉप में भीषण आग, लग्जरी गाड़ियां जलकर खाक

जयपुर ।

राजस्थान की राजधानी जयपुर के बालाजी मार्केट स्थित एक मर्सिडीज वर्कशॉप में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे करीब आठ लग्जरी कारें और कई महंगे स्पेयर पार्ट्स व एक्सेसरीज जलकर खाक हो गए। आग की लपटों और धुएं का गुबार इतना घना था कि यह लगभग पांच किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा था। घटना की सूचना मिलते ही सांगानेर सदर पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दीं।

आग पर काबू पाने के लिए करीब 10 फायर टेंडर तैनात किए गए, जिन्होंने लगभग दो घंटे तक चली मशक्कत में दो दर्जन से अधिक चक्कर लगाए।

वर्कशॉप में 50 से अधिक नई और पुरानी लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं, जिनमें से कई को दमकलकर्मियों और पुलिस की मुस्तैदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़े नुकसान को टाला जा सका। एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके की बिजली आपूर्ति भी काट दी गई थी। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, हालांकि इसके सही कारणों का पता लगाने के लिए अभी जांच जारी है।

पुलिस और फायर विभाग के अधिकारी वर्कशॉप के अंदर मौजूद गाड़ियों और अन्य सामान को हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। जांच पूरी होने पर और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

एफईएमए के तहत कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में 16 ठिकानों पर ईडी के छापे

जांच का एक अहम पहलू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 29ए से जुड़ा

कोलकाता।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोनल कार्यालय ने मैकनली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एमबीईसीएल) के अधिग्रहण से जुड़े मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए), 1999 के तहत बुधवार को कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में कुल 16 ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया। ईडी के द्वारा यह कार्रवाई कंपनी के अधिग्रहण से जुड़े लोगों और संस्थाओं के परिसरों पर की जा रही है। ईडी के मुताबिक तलाशी संजय पसारी, राजीव पसारी, रवि टोडी और सुधीर सतनालीवाला से जुड़े परिसरों के अलावा बीटीएल ईपीटी लिमिटेड, मंडाल व्यापार प्रा लिमिटेट, ट्रोलेक्स (इंडिया) प्रा लि, सीईएमएफआईएल इंटरप्राइजेज लिमिटेड और महाबलेश्वर मर्चेन्ट प्रा लिमिटेड आदि से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है। जांच एजेंसी यह पता लगा रही है कि एमबीईसीएल का नियंत्रण हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए धन का स्रोत क्या था और रकम का किस तरह से आवागमन हुआ। ईडी को इस मामले में फारेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के संभावित उल्लंघन की आशंका है. इसी आधार पर संबंधित व्यक्तियों और कंपनियों के वित्तीय लेन-देन तथा विदेशी मुद्रा से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। जांच का एक अहम पहलू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 29ए से जुड़ा है। ईडी यह भी जांच कर रही

है कि कहीं एमबीईसीएल की इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया का इस्तेमाल ऐसे व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष तरीके से कंपनी का नियंत्रण वापस दिलाने के लिए तो नहीं किया गया, जो धारा 29ए के तहत अधिग्रहण के लिए अयोग्य हो सकते थे।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

जीवन के लिए बड़ी चुनौती बनेगा भूजल का गिरता स्तर

(लेखक- मनोज कुमार अग्रवाल)

मिट्टी, वनस्पति और खुले भूभाग बारिश के पानी को रोकने और धीरे-धीरे जमीन के भीतर पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन शहरों के विस्तार के नाम पर पेड़ों की कटाई और खुले क्षेत्रों का लगातार कम होना मिट्टी और पानी के इस प्राकृतिक संबंध को कमजोर कर रहा है। इसलिए शहरी विकास की योजना बनाते समय हरित क्षेत्र, तालाब, जलाशय, खुले मैदान और प्राकृतिक जल निकासी क्षेत्रों को बचाना आवश्यक है। संकट केवल भूजल तक सीमित नहीं है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 2025 दुनिया की नदियों के लिए पिछले तीन दशकों के सबसे कम प्रवाह वाले वर्षों में शामिल रहा। ग्लेशियरों की स्थिति भी चिंताजनक है।

भारत में भविष्य में गंभीर जल संकट होने की बहुत अधिक आशंका है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के मुताबिक, यदि जल प्रबंधन में सुधार नहीं किया गया, तो आने वाले कुछ वर्षों में स्थिति अत्यधिक चिंताजनक हो जाएगी।नीति आयोग और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत में जल संकट की स्थिति इस प्रकार है मुख्य चिंताएँ और भविष्य के अनुमान के मुताबिक मांग और आपूर्ति में भारी अंतर आ रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक भारत में पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी।भूजल में भारी गिरावट भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपभोक्ता है। उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भारत विशेषकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है क्योंकि रिचार्ज की तुलना में पानी का दोहन बहुत तेजी से हो रहा है।

जल जीवन का आधार है, लेकिन जिस रफ्तार से हम धरती के नीचे जमा पानी को निकाल रहे हैं, वह आने वाले समय के लिए गंभीर चेतावनी है। भारत में, विशेषकर उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में भूजल स्तर में गिरावट कोई नई बात नहीं है। लेकिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन की नवीनतम रिपोर्ट यह बताती है है कि समस्या अब किसी एक वर्ष के कम वर्षा वाले मौसम तक सीमित नहीं रही। कई क्षेत्रों में लगातार कई वर्षों से भूजल सामान्य स्तर से नीचे बना हुआ है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि हम जमीन से जितना पानी निकाल रहे हैं, प्रकृति उतना वापस जमा नहीं कर पा रही है। स्टेट ऑफ ग्लोबल वॉटर रिसोर्सेज 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 2025 के बीच अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, भारत, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के क कई हिस्सों में लगातार भूजल की कमी दर्ज की गई। अनेक क्षेत्रों में अत्यधिक दोहन को इसका महत्वपूर्ण कारण माना गया है। 2025 में जिन भूजल निगरानी केंद्रों के आंकड़े उपलब्ध थे, उनमें लगभग 34 प्रतिशत पर भूजल स्तर सामान्य से कम या काफी कम पाया गया। वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 25 प्रतिशत था। यानी केवल एक वर्ष में सामान्य से कम भूजल वाले निगरानी केंद्रों की हिस्सेदारी में अल्लेखनीय वृद्धि हुई। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये आंकड़े उन्हीं क्षेत्रों पर आधारित हैं, जहां नियमित निगरानी उपलब्ध है। फिर भी लंबे समय से जारी गिरावट का रुझान चिंता पैदा करता है। भारत के लिए यह चेतावनी और गंभीर है। देश की कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और तेजी से फैलते शहरों की जलापूर्ति बड़े पैमाने पर भूजल पर निर्भर है। उत्तरी भारत में 2025 के दौरान स्थलीय जल भंडारण सामान्य से कम दर्ज किया गया। यदि भूजल निकालने और उसके पुनर्भरण के बीच अंतर लगातार बढ़ता रहा, तो आने वाले वर्षों में पेयजल, सिंचाई और उद्योग तीनों पर दबाव बढ़ सकता है। भूजल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह दिखाई नहीं देता। नदी सूखती है तो हमें संकट दिखाई देता है, तालाब खाली होता है तो चिंता होती है, लेकिन जमीन के सैकड़ों फुट नीचे गिरते जलस्तर का एहसास तब होता है जब है जब हैंडपंप, कुएं और बोरवेल जवाब देने लगते हैं। स्थिति यह है कि दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े महानगरों में बोरवेल सूख रहे हैं या उनका पानी दूषित हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार, 2050 तक देश के 50त्न जिलों में गंभीर जल संकट हो सकता है। शहरों में बढ़ता कंक्रीटीकरण इस समस्या को और गंभीर बना रहा है। ऊंची-ऊंची इमारतें बन रही हैं, खाली जमीन लगातार घट रही है और मिट्टी की जगह सीमेंट कंक्रीट ले रहा है। सड़कें, पार्किंग स्थल, आवासीय परिसर और व्यावसायिक भवन शहरों के बड़े हिस्से को ऐसी पकी सतह में बदल रहे हैं, जहां बारिश का पानी जमीन के भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाता। बारिश होती है, पानी आता भी है, लेकिन वह नालियों और जलनिकासी व्यवस्था के रास्ते तेजी से शहर से बाहर निकल जाता है। जिस पानी को जमीन के भीतर जाकर भूजल भंडार भरना चाहिए था, वह कुछ घंटों में बह जाता है। विडंबना यह है कि एक ओर शहरों में बारिश के समय जलजमाव होता है, वहीं दूसरी ओर गर्मियों में भूजल की कमी की शिकायत सामने आती है। पेड़ केवल हवा को स्वच्छ करने या तापमान कम करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। वे स्थानीय जलचक्र का भी अहम हिस्सा हैं। मिट्टी, वनस्पति और खुले भूभाग बारिश के पानी को रोकने और धीरे-धीरे जमीन के भीतर पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन शहरों के विस्तार के नाम पर पेड़ों की कटाई और खुले क्षेत्रों का लगातार कम होना मिट्टी और पानी के इस प्राकृतिक संबंध को कमजोर कर रहा है। इसलिए शहरी विकास की योजना बनाते समय हरित क्षेत्र, तालाब, जलाशय, खुले मैदान और प्राकृतिक जल निकासी क्षेत्रों को बचाना आवश्यक है। संकट केवल भूजल तक सीमित नहीं है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 2025 दुनिया की नदियों के लिए पिछले तीन दशकों के सबसे कम प्रवाह वाले वर्षों में शामिल रहा। ग्लेशियरों की स्थिति भी चिंताजनक है। लगातार चौथे वर्ष दुनिया के सभी प्रमुख हिमनद क्षेत्रों में बर्फ के द्रव्यमान में कमी दर्ज की गई। संगठन की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने वैश्विक स्थलीय जल भंडारण की स्थिति की तुलना एक ऐसे बचत खाते से की है, जिसे लगातार खाली किया जा रहा है। यह तुलना हमें समस्या की गंभीरता समझाती है। हम केवल आज की जरूरत के लिए पानी नहीं निकाल रहे, बल्कि भविष्य के लिए प्रकृति द्वारा जमा की गई पूंजी को भी खर्च कर रहे हैं। स्थिति गंभीर जरूर है, लेकिन समाधान असंभव नहीं है। सबसे पहले वर्षाजल संचयन को केवल भवन निर्माण की औपचारिक शर्त मानने के बजाय जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। बड़ी इमारतों, अपार्टमेंट, होटल, अस्पताल, विद्यालय, उद्योग और सरकारी भवनों में ऐसी व्यवस्था जरूरी होनी चाहिए जिससे वर्षा का अधिकतम पानी भूजल पुनर्भरण में इस्तेमाल हो। तालाबों, पुराने कुओं, नालों और पारंपरिक जलस्रोतों का संरक्षण भी आवश्यक है। शहरों में ऐसे स्थानों की पहचान करनी होगी जहां बारिश के पानी को रोककर जमीन के भीतर पहुंचाया जा सके। केंद्रीय भूजल बोर्ड भी कृत्रिम पुनर्भरण और जल संरक्षण संरचनाओं पर लगातार जोर देता रहा है। केवल सरकार के प्रयास से यह संकट समाप्त नहीं होगा। नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अनावश्यक पानी बहाना, पाइप से लगातार वाहन या सड़क धोना, पानी की लीकेज को नजरअंदाज करना और वर्षाजल को व्यर्थ बहने देना हमारी आदतों का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। नए भवन बनाते समय यह सोचना जरूरी है कि वहां रहने वाले लोगों को पानी कहां से मिलेगा और बारिश का पानी कहां जाएगा। विकास का अर्थ केवल अधिक इमारतें और चौड़ी सड़कें नहीं होना चाहिए। वास्तविक विकास वही है जिसमें पानी, पेड़, जमीन और मनुष्य के बीच संतुलन बना रहे। भूजल बनने में वर्षों लगते हैं, लेकिन उसे खत्म करने में बहुत कम समय लगता है। आज यदि हमने इस अदृश्य प्राकृतिक संपद संपदा को बचाने के लिए गंभीर कदम नहीं उठाए, तो कल पानी का संकट हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। धरती का जल भंडार वास्तव में हमारा साझा बचत खाता है। इससे लगातार निकासी करते रहने के साथ उसमें पानी वापस जमा करना भी जरूरी है। सरकार, स्थानीय निकाय, उद्योग, भवन निर्माता और आम नागरिक सभी को इस जिम्मेदारी में भागीदारी करनी होगी। अंततः हमें यह साधारण बात फिर समझनी होगी, जल से ही धरती है, जल से ही जीवन है और इसका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। सामूहिक प्रयास ही धरती के इस अमूल्य खजाने को सूखने से बचा सकते हैं।

आपको बता दें कि भारत में लगभग 80त्न से अधिक पानी का उपयोग खेती (सिंचाई) के लिए होता है, जिसमें पानी की भारी बर्बादी होती है।प्रदूषण के कारण उपलब्ध पानी का एक बड़ा हिस्सा प्रदूषित हो चुका है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों के भूजल में आर्सेनिक और यूरेनियम जैसी जहरीली चीजें पाई गई हैं।जलवायु परिवर्तन अनियमित मानसूनी बारिश और भीषण गर्मी के कारण जल स्रोत तेजी से सूख रहे हैं।

विश्व बैंक और नीति आयोग के अनुसार, जल संकट के कारण 2050 तक भारत की जीडीपी में 6त्न तक की गिरावट आ सकती है।

इस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है और जल जीवन मिशन तथा अटल भूजल योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। भविष्य में इस संकट से बचने के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग (वर्षाजल संचयन), अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और सूक्ष्म सिंचाई (जैसे ड्रिप इरिगेशन) को बड़े पैमाने पर अपनाना जरूरी है।हर नागरिक को जल का महत्व समझते हुए जल की बर्बादी को रोकने के लिए जागरूक होना होगा।!

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं पिछले 40 वर्ष से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हैं)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

जवाबदेही तय हो

आये दिन देश के विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और आर्थिक संसाधन जुटाने में पारदर्शिता के अभाव की खबरें सुर्खियां बनती रहती हैं। कुछ विश्वविद्यालयों ने अपनी सुविधा के हिसाब से कायदे-कानून बनाने और शैक्षिक जवाबदेही से बचने के रास्ते भी निकाल लिए हैं। इसी आलोक में देश भर के निजी विश्वविद्यालयों के लिए सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों का स्वागत ही किया जाना चाहिए। दरअसल, कई तरह के आक्षेपों के बाद शीर्ष अदालत ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के संचालकों से पूछा है कि वे बताएं कि उनके विश्वविद्यालयों में वित्तीय संसाधन कैसे जुटाये जाते हैं? संसाधनों का प्रबंधन किस तरह से किया जाता है? इसके अलावा ये विश्वविद्यालय इस धन का प्रयोग किस तरह से करते हैं? सही मायने में अदालत का यह निर्देश विश्वविद्यालयों के आय और व्यय के सामान्य ऑडिट से कहीं आगे की बात करता है। दूसरे शब्दों में अदालत के निर्देशों में यह जानने का प्रयास किया गया है कि प्रवेश के समय छात्रों को सुविधाओं के जो सब्जबाग दिखाए जाते हैं उसके मुकाबले हकीकत में कितनी सुविधाएं मिलती हैं। कह सकते हैं कि यह एक आवश्यक रियलिटी चेक है। वास्तव में कोर्ट की जिज्ञासा के पीछे ठोस कारण भी हैं। दरअसल, समाज में यह धारणा बलवती होती जा रही है कि शिक्षा का क्षेत्र धीरे-धीरे एक बिजनेस मॉडल का रूप लेने लगा है। आक्षेप तो यहां तक हैं कि शिक्षा का ये कारोबार रियल एस्टेट मॉडल में बदल गया है। जहां सिर्फ इस बात से ही फर्क पड़ता है कि कितने छात्र दाखिला ले रहे हैं और विभिन्न प्रकार के शुल्क लगाने से इन संस्थानों को कितना मुनाफा हो रहा है। निस्संदेह, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तार्किक ही है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को शिक्षा के व्यापक सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। वे सिर्फ मुनाफे के लिये ही काम नहीं कर सकते। कोर्ट का कहने का अभिप्राय है कि छात्रों के किसी भी तरह के शोषण को रोकने के लिये मजबूत नियामक संस्था की निगरानी जरूरी है। निस्संदेह, इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश में उच्च शिक्षा की मांग तेजी से बढ़ी है। वहीं सरकारी विश्वविद्यालय इस मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। वजह साफ है कि वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते सरकारी संस्थान ज्यादा संख्या में छात्रों को मौका देने में विफल नजर आते हैं। जिसके चलते देश में निजी विश्वविद्यालयों को पांव पसारने का मौका मिल रहा है। वहीं एक हकीकत यह भी है कि कड़ी स्पर्धा वाले निजी क्षेत्र ने बीते कुछ वर्षों में आधी-अधूरी सच्चाइयों का सहारा लेकर अपना कारोबार बढ़ाया है। पर्याप्त शैक्षिक ढांचा न होने, योग्य-अनुभवी शिक्षकों की कमी और प्रभावी अकादमिक शोध की अनदेखी के बावजूद विश्वविद्यालय परिसरों में उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है। वहीं दूसरी ओर प्लेसमेंट के बाबत भी आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। दरअसल, यदि फैकल्टी डेवलपमेंट की कमी एक समस्या है, तो उससे अधिक चिंता करने वाली बात यह भी है कि कम स्टाफ पर ज्यादा काम करने का अतिरिक्त बोझ भी है। अंततः इस सब का खामियाजा छात्रों को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनके हितों से ही समझौता किया जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद निजी विश्वविद्यालयों के लिये फीस स्ट्रक्चर, कर्मचारियों के वेतन, अन्य खर्चों व सरकार से मिलने वाले फायदों या भर्ती और शिक्षा के मानकों के बारे बढ़ा-चढ़ाकर जानकारी देना मुश्किल नहीं होगा। कागजी कार्यवाही पूरी करने की उनकी महारत पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है।

बेटियों की उड़ान ने बदली सफलता की परिभाषा

(लेखक- कांतिलाल मांडोत)

- खेल के मैदान से नेतृत्व की कुर्सी तक महिलाओं का बढ़ता प्रभाव

- आत्मविश्वास और संघर्ष से महिलाएं लिख रही हैं नई कामयाबी की कहानी

नागोया में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत ने भारतीय महिला क्रिकेट की उपलब्धियों में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ दिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 79 रन की शानदार पारी खेली, जबकि शेफाली वर्मा ने 48 और ऋचा घोष ने 49 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम 69 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने तीन विकेट लिए, जबकि शेफाली वर्मा, श्रेयंका पाटिल और श्री चरणी ने दो-दो विकेट लेकर भारत की जीत सुनिश्चित की। यह जीत केवल एक क्रिकेट मुकाबले की सफलता नहीं है, बल्कि उन बेटियों की मेहनत और क्षमता का प्रमाण है, जिन्होंने खेल के मैदान में अपनी पहचान मजबूत की है।

भारतीय महिला टीम की यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बेटियों के प्रति समाज की सोच में आए बदलाव को समझा जा सकता है। कभी महिलाओं को कमजोर समझकर उनके अवसर सीमित कर दिए जाते थे, लेकिन आज वही महिलाएं देश के लिए पदक जीत रही हैं, रिकॉर्ड बना रही हैं और अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिरंगा ऊंचा कर रही हैं। क्रिकेट के मैदान पर कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने वाली महिला खिलाड़ी यह साबित कर रही हैं कि नेतृत्व किसी एक वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं है। अनुशासन, प्रतिभा, मेहनत और जिम्मेदारी के आधार पर महिलाएं हर चुनौती का सामना कर सकती हैं।

महिलाओं की प्रगति केवल खेल तक सीमित नहीं है। शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, प्रशासन, सेना, न्यायपालिका, उद्योग, राजनीति, कला, तकनीक और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। देश की अनेक महिलाएं बड़ी कंपनियों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद तक पहुंचकर संस्थानों का नेतृत्व कर रही हैं। वे हजारों कर्मचारियों के कामकाज, करोड़ों रुपये के कारोबार और बड़े निर्णयों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। यह बदलाव बताता है कि अवसर मिलने पर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन कर सकती हैं।

महिला नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके साथ जिम्मेदारी का भाव भी दिखाई देता है। परिवार संभालने से लेकर पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने तक महिलाएं अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं। यही अनुभव उन्हें परिस्थितियों को समझने, धैर्य के साथ निर्णय लेने और कठिन समय में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। क्रिकेट की पिच पर दबाव के बीच निर्णय लेने वाली खिलाड़ी हो या किसी बड़े संस्थान की जिम्मेदारी संभालने वाली अधिकारी, दोनों ही उदाहरण बताते हैं कि महिलाओं ने जवाबदेही को अपनी सफलता का महत्वपूर्ण आधार बनाया है।

आज बेटियां केवल अपने लिए आगे नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि उनके कदमों से समाज की दूसरी बेटियों के लिए रास्ते खुल रहे हैं। किसी छोटे शहर या गांव की लड़की जब किसी महिला खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सफलता हासिल करते देखती है तो उसके भीतर भी आगे बढ़ने का विश्वास पैदा होता है। जब कोई महिला चिकित्सक, इंजीनियर, अधिकारी, वैज्ञानिक या कंपनी की प्रमुख बनती है तो दूसरी महिलाओं को यह संदेश मिलता है कि सीमाएं जन्म से तय नहीं होतीं। मेहनत, शिक्षा और अवसर के माध्यम से उन्हें बदला जा सकता है।

महिलाओं की सफलता का असर परिवार और समाज दोनों पर पड़ता है। शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला अपने परिवार के निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाती है और अगली पीढ़ी को बेहतर शिक्षा तथा संस्कार देने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। आर्थिक रूप से सक्षम महिला परिवार की मजबूती बढ़ाती है। वहीं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय महिलाएं समाज की समस्याओं को नए दृष्टिकोण से सामने लाती हैं। इस प्रकार एक महिला की सफलता का प्रभाव केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके आसपास की अनेक महिलाओं के जीवन को प्रभावित करता है।

खेलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस परिवर्तन का स्पष्ट उदाहरण है। क्रिकेट, कुश्ती, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, निशानेबाजी, एथलेटिक्स और अन्य खेलों में भारतीय बेटियों ने देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर यह साबित किया है कि प्रतिभा अवसर की तलाश करती है और अवसर मिलने पर परिणाम सामने आता है। महिला खिलाड़ियों की सफलता ने अभिभावकों की सोच भी बदली है। अब बेटियों को केवल पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित रखने के बजाय उन्हें खेल और करियर के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

महिलाओं की प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू आत्मनिर्भरता भी है। आज बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयं का कारोबार शुरू कर रही हैं, रोजगार दे रही हैं और आर्थिक गतिविधियों में योगदान कर रही हैं। गांवों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं छोटे व्यवसाय चला रही हैं, जबकि शहरों में महिलाएं नई कंपनियां स्थापित कर रही हैं। तकनीक ने भी महिलाओं के लिए अवसरों का विस्तार किया है। घर से काम करने, ऑनलाइन कारोबार और डिजिटल माध्यमों ने अनेक महिलाओं को अपनी प्रतिभा को आय के साधन में बदलने का अवसर दिया है।

हालांकि महिलाओं की उपलब्धियों को केवल पुरस्कारों और पदकों से नहीं मापा जा सकता। असली सफलता तब होगी जब हर बेटी को शिक्षा, सुरक्षा, समान अवसर और अपनी पसंद का क्षेत्र चुनने की स्वतंत्रता मिले। परिवारों और समाज को बेटियों की प्रतिभा पर भरोसा करना होगा। उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना होगा और असफलता के डर से रोकने के बजाय संघर्ष से सीखने का अवसर देना होगा।

मौन का तन मन की सुन्दरता के लिये महत्व

प्रत्येक मनुष्य सुन्दर एवं स्वस्थ्य रहना चाहता है। सुन्दरता एवं स्वस्थ्य का राज मौन मै छिपा हुआ है। सामान्यतः चुप रहना मौन है, प्राचीन पुराण बचन के साथ ईष्या, डाह, छल, कपट और हिन्सा को कम करना मोन होता है। मनोवैज्ञानिक 'फायड' का कहना है कि जीवन अन्तर्द्वद्वी श्रृंखलाओं से मिल कर बना है। अन्तर्द्वद्व दो या दो से अधिक विरोधी इच्छाओं का एक साथ उत्पन्न होना है। ये असीम इच्छायें पूर्ण न होने पर तनाव नामक बीमारी देती है। जिससे आज के अधिकांस व्यक्ती ग्रासित है। अन्तर्द्वद्व में फंसे व्यक्ति की स्थिति कई विपरीत दिशाओं से आने वाली नदियों के पानी के साथ मिलने से भॅवर बनती है कि जैसी हो जाती है। भॅवर में फसे व्यक्ति को न बैठे शांति मिलती है न लेटे, न भूख लगती है, न प्यास, न ही ध्यान अध्ययन में मन लगता है। याददास्त क्षमता कम हो जाती है। हार्ट अटेक, आत्म हत्या भी इसी कारण करते हैं।

हर मनुष्य अन्नत शक्तिमान है। यह शक्ति मन एवं पाचों इन्द्रियों के कार्यो में खर्च होती है। मन एवं इन्द्रियों को बस मे करने का कार्य 'मौन' करता है। मौन रहने से मनुष्य के अन्दर की छुपी हुई शक्ति उदय हो जाती है। आज के कल युग में इनद्रिय विषय-भोगों की सामग्री में वहुत वृद्धि हूई है जिसे अपनाने पर इक्छा शक्ति में अधिक बृद्धि हो रही है। जो टेन्सन को जन्म देती है। अतः आज टेन्सन बड़ी बीमारी हो गई है। जो भी व्यक्ति अधिक बोलते है उनके मुख में रहने वाला पाचक रस सूख जाता है। मानसिक सन्तुलन खो जाता है, हृदय गति तेज हो जाती है। मान इन सब परेशानियों से बचने की राम वाण औषधी है। दिन में एक घण्टा मौन रहने पर दो घण्टे की कार्य क्षमता में बृद्धि होती है। रक्त प्रवाह सामान्य स्वस्थ्य होता है, तन, मन, सुन्दर बनता है। अतः संयमित वोल मान को जीवन में अपनाना चाहिये।

केंद्रीय चुनाव आयोग पर ज्ञानेश कुमार और मनीष गर्ग का कब्जा?

(लेखक- सनत जैन)

- चुनाव आयोग ने संसद और चुनाव अधिकारियों के अधिकार छीने

केंद्रीय चुनाव आयोग में तीन सदस्य होते हैं, इन्हें बहुमत के आधार पर काम करना होता है। लेकिन जब से ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर आए हैं, उसके बाद से चुनाव आयुक्तों की भूमिका एक तरह से खत्म कर दी गई है। मनमाने तरीके से ज्ञानेश कुमार निर्णय लेते हैं, इसकी सूचना अन्य दो चुनाव आयुक्त को नहीं होती है। मनमाने फैसले के कारण इस समय चुनाव आयोग में केवल दो अधिकारियों का कब्जा है। उसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं दूसरे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग, जो आईटी विभाग का भी काम देख रहे हैं। इन दो आदमियों के पास चुनाव आयोग का पूरा केंद्रीकरण हो गया है। चुनाव आयोग को पारदर्शी तरीके से काम करने की अनिवार्यता है, लेकिन 2 जनवरी 2026 के बाद जब से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद से ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक नया ईसीआई नेट लॉन्च कर दिया। इसकी जानकारी दोनों चुनाव आयुक्त को नहीं दी गई। चुनाव आयोग के आईटी विभाग ने कई नए मॉडल के सॉफ्टवेयर तैयार किए गए। इसकी जानकारी भी दोनों चुनाव आयुक्तों को नहीं दी गई। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और संधू ने इस संबंध में लिखित आपत्ति भी दर्ज कराई। ऑडिट करने का सुझाव दिया गया, लेकिन इनके कोई सुझाव को ज्ञानेश कुमार ने नहीं माना। दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस बदलाव और मनीष गर्ग द्वारा जो आदेश जारी किया गया था उसके संबंध में जो कार्रवाई की गई उसे मुख्य चुनाव आयुक्त ने नहीं माना। इसके अलावा फॉर्म नंबर 6 में जो नया प्रावधान किया गया उसमें माता-पिता, दादा-दादी के पिछले एसआईआर की सूची में नहीं होने पर जो नया पोर्टल बनाया गया उसमें फॉर्म 6 की जानकारी भरी ही नहीं जा सकती थी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 22 जनवरी 2026 को जो ईसीआई नेट लॉन्च किया, इसमें 40 से ज्यादा एप पोर्टल में डाले गए, जिसके कारण चुनाव आयुक्त की पूरी कार्यप्रणाली ही बदल गई। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि इसके संबंध में ना तो कोई ऑडिट कराया गया ना ही दोनों चुनाव आयुक्तों से सलाह ली गई। ना इसको लेकर कोई बैठक हुई। इसके निर्णय ज्ञानेश कुमार और उनके पसंदीदा अफसर मनीष गर्ग ले रहे थे। इस पर पूरी गोपनीयता बरती जा रही थी। जनवरी 2026 से पोर्टल ने पूरी तरह से देश भर के जितने भी बीएलओ हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके भी अधिकार को केंद्रीकृत कर लिया गया था। पोर्टल से ही नोटिस जारी हो रहे थे। पोर्टल में एक्सेस सीमित कर दिया गया था। यहां तक कि चुनाव परिणाम जो पहले जिले में मतगणना करने और घोषित करने के अधिकार थे वह भी चुनाव आयोग ने अपने हाथ में ले लिए थे। जिले के निर्वाचन अधिकारी और ईआरओ को पोर्टल में सीमित अधिकार दिया गया था।

एक तरह से ज्ञानेश कुमार ने संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत जो अधिकार बीएलओ और जिला निर्वाचन अधिकारी के पास थे, उनके अधिकार भी पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी ही तय करते थे जिसके कारण एसआईआर में पोर्टल ही डिसाइड करता था किसे नोटिस भेजना है उनके जवाब को स्वीकार करना है या नहीं। यह सब काम चुनाव आयोग का 2026 वाला पोर्टल कर रहा था। जिसमें नए-नए ऐप डाल दिए गए थे। उसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। सारी व्यवस्था केंद्रीय चुनाव आयोग के माध्यम से हो रही थी। बिहार, पश्चिम बंगाल और गोवा और कई अन्य राज्यों के चुनाव अधिकारियों ने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने किसी पत्र का जवाब नहीं दिया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामले एसआईआर को लेकर चल रहे थे। प्रक्रिया को लेकर सुनवाई हो रही थी इस मामले में भी दोनों चुनाव आयुक्तों को ना तो कोई जानकारी दी गई ना ही उनके सुझाव मांगे गए। केंद्रीय चुनाव आयोग में जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मनमानी कर रहे थे, दोनों चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को लगभग 14 पत्र लिखे, लेकिन किसी के भी कोई जवाब नहीं आए। जो ज्ञानेश कुमार करना चाहते थे वह करते रहे। पश्चिम बंगाल में 38 लाख से ज्यादा मतदाताओं की ट्रिब्यूनल में अपील लगी।

इसका फैसला भी एक तरफ लिया गया। कुल मिलाकर केंद्रीय चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार ही सर्वेसर्वा हो गए थे। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिस बात का अधिकार उन्हें नहीं था उन्होंने फॉर्म नंबर 6 और अन्य फॉर्म अपनी मन मर्जी से बदल दिए। पोर्टल में पूरे अधिकार केंद्रीय चुनाव आयोग के पास आ गए।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सिगरेट के शौकीनों को कश लगाना पड़ेगा मंहगा.....गोल्ड फ्लेक सिगरेट हुई महंगी

मुंबई।

देश की सबसे बड़ी सिगरेट निर्माता कंपनी आईटीसी ने अपने मशहूर ब्रांड गोल्ड फ्लेक सिगरेट की कीमतों में फिर बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि गोल्ड फ्लेक प्रीमियम और इसके संबंधित वेरिएंट्स पर लागू हुई है, इससे अब 10 और 20 सिगरेट वाले पैकेट महंगे हुए हैं। दाम बढ़ने के बाद, 10 सिगरेट के पैक की कीमत 115 से बढ़कर 135 रुपए हो गई है। कंपनी ने इस साल गोल्ड फ्लेक प्रीमियम के दाम में 17.4 प्रतिशत का इजाफा किया है। यानी, अब सिगरेट के शौकीनों को कश लगाने के लिए पहले से अधिक कीमत चुकानी होगी और उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

28 से 30 तक राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल, 25 सितंबर तक निपटा लें सभी जरूरी काम

-26 को शनिवार, 27 को रविवार बंद, पांच दिनों तक बैंक का काम रहेगा प्रभावित

नई दिल्ली।

अगर बैंक से जुड़ा आपका कोई जरूरी काम बाकी है, तो उसे जल्द से जल्द निपटा लेना आपके लिए बेहतर होगा। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे 28 से 30 सितंबर के बीच प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए 25 सितंबर तक अपनी शाखा से जुड़े सभी जरूरी काम पूरे कर लें। बैंक ने अपने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि हड़ताल में शाखाओं में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

यह हड़ताल 28 से 30 सितंबर तक है, लेकिन इससे पहले 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार है। इसका मतलब है कि लगातार पांच दिनों तक बैंक शाखाओं में काम प्रभावित हो सकता है। ऐसे में बैंक के काम अंतिम समय तक न टालें। हड़ताल के दौरान शाखाओं पर कामकाज प्रभावित होने की स्थिति में ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पीएनबी ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध रखने की पूरी कोशिश की जाएगी।

सोने और चांदी की कीमतों में तेजी

नई दिल्ली ।

घरेलू बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोना 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच गया है। दूसरी ओर चांदी की कीमतों में भी तेजी रही और ये 2.41 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गयी है। प्राप्त जानकारों के अनुसार, सोने की कीमतों में इसह तेजी का कारण पिछले कुछ दिनों से इसमें लगातार को रही बढ़त है। एमसीएक्स पर बीते कारोबारी सत्र में सोना 696 रुपये की बढ़त के साथ 1,52,716 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुधवार को सुबह बाजार खुलते ही सोने में करीब 80 रुपये की तेजी दिखी और यह सिलसिला जारी रहा। सुबह 10.50 बजे तक सोने का वायदा भाव 74 रुपये और बढ़कर 1,52,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यह कीमत 24 कैरेट यानी 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सोने के लिए है, जो निवेशकों और खरीदारों के लिए एक महत्वपूर्ण मानक होता है।

इसके अलावा चांदी में भी काफी तेजी दर्ज की गयी। सोने की तुलना में चांदी में तो एक हजार रुपये के आसपास का उछाल दिख रहा है। आज सुबह चांदी के वायदा भाव में 900 रुपये से भी अधिक की तेजी दर्ज की गई थी। सुबह 10.50 बजे तक यह उछाल थोड़ा कम होकर 729 रुपये पर आ गया। इसके बाद एमसीएक्स पर चांदी 2,40,642 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

जानकारों का कहना है कि आने वाले त्यौहारी सीजन को देखते हुए कीमतों में और तेजी आ सकती है। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और मजबूत मांग के चलते आने वाले समय में भी इन कीमती धातुओं के दाम ऊपर बने रह सकते हैं।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 299, निफ्टी 117 अंक उछल

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार में ये तेजी दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीददारी हावी रहने से आई है। इससे जिससे निवेशकों ने राहत की सांस ली है। बाजार में लौटी रौनक के पीछे वैश्विक स्तर पर उभरते सकारात्मक संकेतों के साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में आई स्थिरता को भी माना जारहा है। अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा बातचीत शुरू होने की उम्मीदों ने भू-राजनीतिक तनाव में कमी आने की संभावना जताई। इन अनुकूल घटनाक्रमों ने घरेलू निवेशकों की धारणा को मजबूत किया और खरीदारी का माहौल बना, जिसके चलते बाजार के दोनों प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक शानदार बढ़त के साथ बंद हुए।इस सकारात्मक रुख के चलते, कारोबार के अंत में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 299.17 अंकों की शानदार बढ़त के साथ ही 74,828.25 के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का बेंचमार्क निफ्टी भी 117.80 अंक उछलकर 23,446.80 के स्तर पर बंद हुआ। ।बड़े शेयरों के साथ-साथ, मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन अच्छी-खासी तेजी देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप 50 सूचकांक भी 101 अंकों की प्रभावशाली बढ़त के साथ 17,979.65 अंक पर बंद हुआ। यह दिखाता है कि निवेशकों की रुचि केवल बड़े शेयरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि मझोले आकार की कंपनियों में भी वह निवेश कर रहे थे। शीर्ष लाभ कमाने वाले शेयरों में सेल (6.57 फीसदी की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा, जिसके बाद पीबी फिनटेक ने 4.23 फीसदी और 360 वन वाम ने 3.86 फीसदी की वृद्धि दर्ज की। इन कंपनियों के शेयरों में आई उछाल ने संबंधित क्षेत्रों में सकारात्मक भावनाओं को बल दिया। इनके अलावा, बंधन बैंक के शेयरों में 3.62 फीसदी और मोतीलाल ओसवाल में 3.53 फीसदी की तेजी ने भी निवेशकों का ध्यान खींचा।हालांकि, एक मजबूत दिन के बावजूद, कुछ शेयर दबाव में रहे और लाल निशान पर बंद हुए। शीर्ष गिरावट दर्ज करने वाले शेयरों में आइनॉक्स विंड 3.70 फीसदी, एथर एनर्जी 2.88 फीसदी और परसिस्टेंट 2.35 फीसदी की गिरावट के साथ शामिल थे। इसके अतिरिक्त, वन 97 पेटीएम और स्विगी) के शेयरों में भी क्रमशः 2.17 फीसदी और 1.95 फीसदी की कमी आई। इन शेयरों में गिरावट के पीछे कंपनी-विशिष्ट कारण या निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली हो सकती है, जो बाजार की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार बढ़त के साथ खुला। सुबह सेंसेक्स लगभग 200 अंकों की बढ़त के साथ खुला, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) निफ्टी में भी तेजी रही।

चाहकर भी कोई सरकार कृषि उत्पादों की कीमतें तय नहीं कर सकती

चीनी की कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर गडकरी ने साफ कर दिया

नई दिल्ली।

देश में चीनी की कीमतों में उतार-चढ़ाव और चीनी उद्योग द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की मांग के बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चीनी या अन्य कृषि उत्पादों के दाम तय नहीं कर सकती। गडकरी ने कहा कि वर्तमान में हम एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में हैं, जहां चाहकर भी कोई सरकार कृषि उत्पादों की कीमतें तय नहीं कर सकती। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि चीनी के दाम ब्राजील, मक्के के दाम अमेरिका और पाम ऑयल की कीमतें मलेशिया में तय होती हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए किसानों के लिए ऐसी मांगों को उठाना आसान होता है, लेकिन सत्ता में रहने पर इन्हें व्यावहारिक रूप से लागू करने में कठिनाइयां होती हैं। वैश्विक बाजार का गणित समझाते हुए उन्होंने बताया कि ब्राजील में 2,000 से 3,000 एकड़ के बड़े फार्म हैं और वहां आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होता है। इस वजह से ब्राजील में चीनी बनाने की लागत महज 23 रुपए प्रति किलो आती है, जबकि भारत में यह लागत 33 से 34 रुपए प्रति किलो पड़ती है। ब्राजील में अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध होते ही भारत में कीमतें अपने आप गिर जाती हैं।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गडकरी ने चीनी उद्योग और किसानों को केवल चीनी बिक्री पर निर्भर न रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए गन्ने के अन्य सह-उत्पादों का इस्तेमाल करना जरूरी है।

दिल्ली में अब बिना वैध सर्टिफिकेट वाहन में नहीं भरी जाएगी सीएनजी

सुरक्षा के मद्देनजर आईजीएल ने शुरू किया वेरिफिकेशन सिस्टम

नई दिल्ली।

दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने कई सीएनजी स्टेशनों पर एक ऑटोमेटेड व्हीकल वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है, जिसके बाद अब बिना ज्यादा जांच के सीएनजी भरवाना मुश्किल हो सकता है। यह नया सिस्टम तय करेगा कि आपकी गाड़ी में सीएनजी तभी भरी जाए जब आपके सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो-टेस्ट सर्टिफिकेट वैध हो। इस नए सिस्टम के तहत जब कोई वाहन चालक सीएनजी भरवाने पंप पर जाएगा, तो पहले की तरह सीधे सीएनजी नहीं भरी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक सीएनजी स्टेशन पर लगे कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और सिस्टम सीएनजी सिलेंडर से जुड़ी जानकारी की जांच करेगा। यदि सिलेंडर का हाइड्रो-टेस्ट सर्टिफिकेट वैध नहीं पाया जाता है, तो वाहन चालक की गाड़ी में सीएनजी नहीं भरी जाएगी। आईजीएल ने फिलहाल 10 स्टेशनों पर यह ऑटोमेटेड व्हीकल वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य गैस लीकेज और ब्लास्ट जैसे खतरों को रोकना और सुरक्षा तय करना है। इसलिए, सीएनजी गाड़ी चलाने वालों को यह तय करना होगा कि वे अपने सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो-टेस्ट समय पर करवाएं और उसका सर्टिफिकेट हमेशा वैध रखें। यह आपके और आपकी गाड़ी की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक सीएनजी भरवाने जाने से पहले अपने सिलेंडर के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जांच लेना समझदारी होगी, ताकि आपको कोई परेशानी न हो। एआई सिस्टम की मदद से गाड़ी की जानकारी को सीएनजी सिलेंडर के रिकॉर्ड से मिलाया जाएगा और पीईएसओ के ऑनलाइन पोर्टल से सिलेंडर का सर्टिफिकेट वैध है या नहीं, यह देखा जाएगा।

स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन जरुरी

भारत में ऐसे प्रोडक्ट बेचने से पहले कंपनियों को लेनी होगी रेगुलेटरी मंजूरी

नई दिल्ली।

सरकार ने स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन जरुरी कर दिया है। इसके तहत भारत में ऐसे प्रोडक्ट बेचने से पहले कंपनियों को रेगुलेटरी मंजूरी लेनी होगी। इस कदम से खराब क्वालिटी वाले स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर की बिक्री पर रोक लगने और ऑप्टिमस इन्फ्राकॉम जैसी घरेलू कंपनियों को मदद मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने भारत में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। 21 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुड्स ऑर्डर, 2021 के नियम उन सामानों या चीजों पर लागू होंगे जो स्मार्टफोन के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर में बताए गए हैं।

इस नोटिफिकेशन के ज़रिए इन्हें ऑर्डर की लिस्ट में जोड़ा गया है, ताकि ये कॉलम 3 में बताए गए संबंधित भारतीय स्टैंडर्ड के अनुरूप हों। यह नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा।

स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर इस नियम के तहत नोटिफाई की जाने वाली 66वीं चीज है। इस लिस्ट में शामिल अन्य चीज़ों में स्मार्टफोन, लैपटॉप, मोबाइल और लैपटॉप चार्जर, एलईडी टेलीविज़न, माइक्रोवेव ओवन, प्रिंटर और सेट-टॉप बॉक्स वगैरह शामिल हैं। स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए जरूरी बीआईएस स्टैंडर्ड लागू करना इस कैटेगरी के लिए एक अहम पड़ाव है और यह क्वालिटी पर आधारित मेड-इन-इंडिया इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।

ऑप्टिएमस ने नोएडा में एक प्रोडक्शन यूनिट लगाई है, जहां अमेरिकी मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी कॉर्निंग की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर बनाए जाएंगे। कंपनी को उम्मीद है कि जनवरी 2027 से इनकी शिपिंग शुरू हो जाएगी।

कंपनी को चालू वित्त वर्ष में अपने टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर बिज़नेस से 1,800-2,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। मोबाइल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों के संगठन आईसीईए के चेयरमैन ने कहा कि 1 अप्रैल 2027 से जरूरी बीआईएस सर्टिफिकेशन लागू होने से ग्राहकों को घटिया क्वालिटी वाले प्रोडक्ट से सुरक्षा मिलेगी और साथ ही घरेलू मैन्युफैक्चरर्स और ग्लोबल कंपनियों के लिए समान अवसर तैयार होगा।उन्होंने कहा कि सालाना 50 करोड़ से ज़्यादा यूनिट के मार्केट के साथ यह कदम 12,000-16,000 करोड़ रुपए की क्वालिटी-बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा।

करीब 60,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगा और जीएसटी रेवेन्यू में अनुमानित 2,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा।

इससे स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब के तौर पर भारत की क्षमता भी मज़बूत होगी। अनुमान है कि 2025 में टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर का घरेलू मार्केट 40 करोड़ पीस का होगा, जिसकी रिटेल वैल्यू 20,000 करोड़ होगी।

सितंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार:पीएमआई 3 माह के शीर्ष स्तर पर पहुंचा

मुंबई ।

सितंबर में भारत के निजी क्षेत्र की कारोबारी गतिविधियां तीन महीने के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई है, जो अर्थव्यवस्था में नई गति का संकेत है। बुधवार को जारी एचएसबीसी फ्लैश परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) सर्वे के अनुसार, यह इंडेक्स अगस्त के 54.3 से बढ़कर 56.5 हो गया है। यह लगातार 62वां महीना है जब पीएमआई 50 के विस्तार निशान से ऊपर बना हुआ है, जो आर्थिक वृद्धि का सूचक है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, दोनों सेक्टर में उत्पादन में सुधार ने उछाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सर्वे में बताया गया कि सितंबर के दौरान भारत के निजी क्षेत्र की कंपनियों में कुल नए व्यवसाय में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहां मांग में सबसे अधिक सुधार देखा गया। सर्विस सेक्टर में भी प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सॉल्यूशंस जैसी सेवाओं की मांग बढ़ी। सामान बनाने वाली कंपनियों ने एल्युमीनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाने-पीने की चीजों, दवाओं और नए प्रोडक्ट मॉडल की मांग में तेजी देखी। एचएसबीसी फ्लैश इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगस्त के 52.8 से बढ़कर सितंबर में 55.7 हो गया, जबकि फ्लैश इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स 54.1 से बढ़कर 55.8 पर पहुंच गया। बढ़ते उत्पादन और नए ऑर्डरों के कारण कुल रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों क्षेत्रों में करीब समान रही। इस सकारात्मक माहौल के बीच, निजी क्षेत्र में इनपुट लागत की वृद्धि दर जनवरी के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गई, सर्विस कंपनियों के लिए लागत दबाव में कमी ने मैन्युफैक्चरर्स की लागत वृद्धि के प्रभाव को संतुलित किया। सितंबर में कंपोजिट स्तर पर बिक्री कीमतों में बढ़ोतरी करीब वैसी ही रही, हालांकि फैक्ट्री गेट चार्जेस में तेजी देखी गई। एचएसबीसी की मुख्य भारतीय अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने बताया, इनपुट की खरीद में तेजी आई है और तैयार माल के स्टॉक का इंडेक्स अब साढ़े 11 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है, जो भविष्य की मांग के प्रति विश्वास को दिखाता है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए कीमतों का दबाव बढ़ा है और आउटपुट की कीमतों में बढ़ोतरी की रफ्तार तेज हुई है। उन्होंने बताया कि कंपनियां मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण अनिश्चितताओं से निपटने के लिए सुरक्षा उपाय बना रही हैं।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को रुपया 12 पैसे की गिरावट के साथ ही 95.74 पर बंद हुआ। आज सुबह शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया तेजी के साथ खुला। आज सुबह रुपया डॉलर के मुकाबले पांच पैसे बढ़कर 95.57 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में जारी गिरावट और एशियाई मुद्राओं में व्यापक सुधार से भी रुपए को बल मिला है। वहीं विदेशी मुद्रा बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और भू-राजनीतिक घटनाक्रम आगे चलकर मुद्रा बाजार की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भी रुपया मजबूत हुआ है। इससे आयात बिल का दबाव कम होता है। इसी दौरान अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद डॉलर में लगातार मजबूती और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की भारतीय इक्विटी बाजार से लगातार बिकवाली से भी रुपये की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं।आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपया 95.58 प्रति डॉलर पर खुला। दिन के कारोबार में यह 95.57 के स्तर तक पहुंचा, जो इसके पिछले बंद भाव से पांच पैसे की बढ़त दिखाता है। गौरतलब है कि मंगलवार को रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 95.62 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

अगस्त में घरेलू हवाई यातायात घटा, स्पाइसजेट और इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी में कमी

मुंबई ।

भारत में घरेलू हवाई यात्री यातायात ने अगस्त महीने में सालाना आधार पर 6.34 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जिससे कुल 1.21 करोड़ यात्रियों ने उड़ान भरी। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों में जानकारी सामने आई है, जो विमानन उद्योग के लिए एक मिश्रित तस्वीर दिखाती है। इस अवधि के दौरान, कुछ प्रमुख एयरलाइंस की बाजार हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दिए।

परिचालन संबंधी चुनौतियों से जूझ रही स्पाइसजेट की हिस्सेदारी जुलाई के 1.6 से घटकर अगस्त में मात्र 1.2 प्रतिशत रह गई, जो उसकी मुश्किलों को दिखाती है। वहीं, प्रमुख वाहक इंडिगो को भी अपनी हिस्सेदारी में गिरावट का सामना करना पड़ा, जो जुलाई के 67.4 प्रतिशत से घटकर बीते महीने 65 प्रतिशत हो गई। हालांकि, इंडिगो अभी भी घरेलू विमानन बाजार में अग्रणी बनी हुई है। इसके विपरीत, एयर इंडिया ने अपनी स्थिति मजबूत की, उसकी हिस्सेदारी जुलाई के 24 से बढ़कर अगस्त में 26.7 प्रतिशत हो गई। अकासा एयर की बाजार हिस्सेदारी 5.5 प्रतिशत पर स्थिर बनी रही।

अगस्त में इंडिगो ने 78.87 लाख यात्रियों के साथ शीर्ष स्थान बरकरार रखा। इसके बाद एयर इंडिया समूह रहा, जिसने 32.32 लाख यात्रियों को सेवा दी, जबकि अकासा एयर ने 6.68 लाख यात्रियों के साथ तीसरा स्थान बनाए रखा। स्पाइसजेट ने महीने के दौरान 1.40 लाख यात्रियों को यात्रा कराई। आंकड़ों के अनुसार, ऑन-टाइम परफॉरमेंस (ओटीपी) के मामले में, इंडिगो 91 प्रतिशत के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद अकासा एयर 90.5 प्रतिशत और एयर इंडिया समूह 83.9 प्रतिशत के साथ रहा।

इस बीच, नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने हाल ही में कहा कि डीजीसीए स्पाइसजेट के वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन पर करीब से नजर रख रहा है।

आरबीआई का बड़ा फैसला: हड़ताल के बीच रविवार को बैंक ओपन

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महत्वपूर्ण कदम उठाकर आगामी रविवार, 27 सितंबर को भी बैंक शाखाएं, कार्यालय, एटीएम लिंक्ड ब्रांच और करेंसी चेस्ट खोलने की अनुमति दे दी है। यह फैसला ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि उन्हें संभावित लंबी बैंकिंग बाधा का सामना न करना पड़े।

दरअसल, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का ऐलान किया है। इसके पहले, 26 सितंबर को शनिवार और 27 सितंबर को रविवार की साप्ताहिक छुट्टी थी। यदि रविवार को भी बैंक बंद होते, तब आम ग्राहकों को लगातार पांच दिनों तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहना पड़ता, इससे नकदी संकट और अन्य महत्वपूर्ण लेनदेन में भारी परेशानी आ सकती थी।

इसी संभावित कठिनाई को देखकर आरबीआई ने यह आपातकालीन निर्णय लिया है। आरबीआई ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) को लिखे अपने पत्र में साफ किया है कि जनता की वास्तविक बैंकिंग जरूरतों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ना चाहिए। बैंकों को कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए सुनिश्चित करने को कहा गया है कि 27 सितंबर को उनकी शाखाएं और करेंसी चेस्ट पूरी तरह से चालू रहें।

निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के करेंसी चेस्ट की सूची भी अलग से भेजी गई है, ताकि सभी आवश्यक सेवाएं सुचारु रूप से चल सकें।

बैंक ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे नकदी निकालना, जमा करना या अन्य महत्वपूर्ण लेनदेन जैसे अपने जरूरी काम 27 सितंबर को ही निपटा लें। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद तीन दिनों तक बैंकों में सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है, जिससे अगले कई दिनों तक वित्तीय लेन-देन में रुकावट आने की आशंका है। यह कदम ग्राहकों को आगामी हड़ताल के कारण होने वाली असुविधा से बचाने के लिए उठाया गया है।

चीनी के खुदरा दामों में 14 से 17 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट

लोगों को मिली राहत, बढ़ते भावों ने आम जनता की बढ़ा दी थी चिंता

नई दिल्ली।

त्योहारी सीजन में चीनी के बढ़ते भावों ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि इस दौरान मिठाईयों और अन्य पकवानों में चीनी की खपत ज्यादा होती है। अब लगता है कि स्थिति नियंत्रण में आ रही है, क्योंकि चीनी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले एक महीने में चीनी की खुदरा कीमत में कमी आई है। चीनी मंडी के आंकड़ों के मुताबिक 22 अगस्त से 21 सितंबर के बीच खुदरा चीनी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली, कानपुर जैसे प्रमुख शहरों में खुदरा चीनी के भाव में 14 से 17 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट देखी गई है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है।यह गिरावट केवल खुदरा बाजार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चीनी के थोक भाव में भी काफी कमी आई है। इसी अवधि के दौरान अलग-अलग शहरों में थोक कीमत 1,600 रुपए प्रति क्विंटल से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल तक कम हुई हैं। यह थोक गिरावट सीधे तौर पर खुदरा कीमतों को प्रभावित करती है, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होता है। सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि चीनी की बढ़ती कीमतों से अब थोड़ी राहत मिली है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में खुदरा चीनी की कीमतें करीब 65 रुपए प्रति किलो थीं, जो अब घटकर करीब 58.50 रुपए प्रति किलो रह गई हैं। इसके अलावा, एक्स-मिल कीमतों में भी करीब 25फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। जब खुदरा और थोक दोनों कीमतों में कमी आई है, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ दिनों में जनता तक पहुंचने वाली चीनी की अंतिम कीमतों में भी और गिरावट देखने को मिलेगी।

भारत की बेटियां बना रही हैं आईफोन:उत्पादन में 80 प्रतिशत महिला कर्मचारी

मुंबई ।

आज दुनिया भर में महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ी है, लेकिन भारत ने इस मामले में एक नया कीर्तिमान बनाया है, खासकर आईफोन जैसे वैश्विक उत्पाद के निर्माण के क्षेत्र में। देश में आईफोन बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक फॉक्सकॉन में 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी भारत की बेटियां हैं, जो स्मार्टफोन के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं। यह आंकड़ा भारतीय कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती शक्ति और उनके योगदान को दिखाता है।

यह स्थिति फॉक्सकॉन के तमिलनाडु स्थित प्लांट में विशेष रूप से देखने को मिलती है, जहां 2024 के आंकड़ों के अनुसार कुल 41,281 कर्मचारियों में से 33,360 महिलाएं हैं। इस तरह, बेंगलुरु के देवनहल्ली में स्थित फॉक्सकॉन के एक अन्य प्लांट में बीते साल तक कार्यरत करीब 30,000 लोगों में से 80 प्रतिशत यानी करीब 24,000 महिलाएं थीं। यह आंकड़ा न केवल कंपनियों के भीतर महिलाओं की मजबूत उपस्थिति को दिखाता है, बल्कि उनके लिए रोजगार के व्यापक अवसरों का भी संकेत देता है।यह सिर्फ फॉक्सकॉन तक सीमित नहीं है। भारत में एप्पल के पूरे इकोसिस्टम की बात करें, जिसमें फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं, करीब 1.40 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

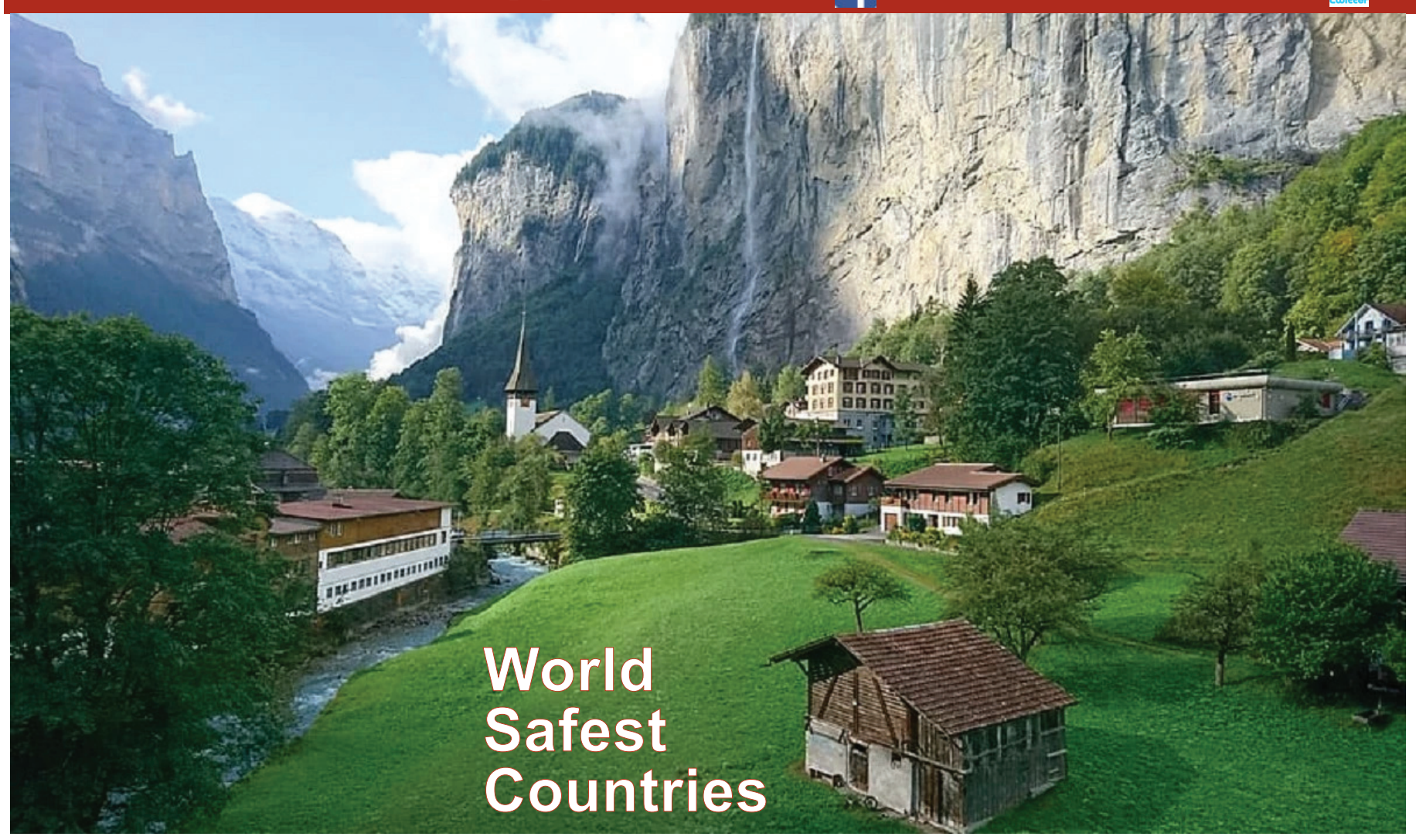

इन देशों में सुरक्षा की नहीं होगी चिंता, बेफिक्र होकर बनाएं घूमने का प्लान

कई लोग विदेश घूमने की इच्छा रखते हैं। विदेश घूमने के लिहाज से अधिकतर देश शानदार हैं। हालांकि विदेशों की खूबसूरती किसी भी टूरिस्ट के मन को आसानी से भा सकती है। लेकिन जब भी विदेश घूमने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आता है कि क्या वह जगह सुरक्षा के लिहाज से सही है। क्योंकि सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायॉरिटी होती है। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आपको सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आइए जानते हैं कि वह कौन-कौन से देश हैं, जहां पर आप बेफिक्र होकर घूम सकते हैं।

आइसलैंड

आइसलैंड की आबादी 3,72,295 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार, यह दुनिया का सबसे सुरक्षित देश हैं। बता दें कि यहां पर क्राइम रेट काफी कम है। इसके साथ ही यह हाई-सिक्योरिटी वाला देश भी है। सभी तरह के अपराधों के प्रति यहां के नागरिकों का एक मजबूत सामाजिक दृष्टिकोण है। यह देश धार्मिक स्वतंत्रता देने के साथ ही महिलाओम और पुरुषों को समान अधिकार देता है। अगर आप भी विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आइसलैंड सुरक्षित देश है।

न्यूजीलैंड

आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की जनसंख्या 5,124,100 के आसपास है। यह देश भी घूमने और रहने के लिहाज से सुरक्षित है। यहां पर आप बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। न्यूजीलैंड का भी क्राइम रेट कम है। हालांकि साल 2019 में क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों पर हुए आतंकवादी हमले के कारण यहां का क्राइम स्कोर थोड़ा कम हो गया है। यह पर आप सुरक्षा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड में शांति वाले इलाके में पुलिस अपने पास हथियार भी नहीं रखती है।

पुर्तगाल

साल 2014 के अनुसार, पुर्तगाल दुनिया का 18वां सबसे सुरक्षित देश है। ऐसे में आप बिना सुरक्षा की चिंता किए बगैर यहां पर घूम सकते हैं। 10,270,865 के करीब आबादी वाला यह देश विभिन्न कारणों से सबसे सुरक्षित देशों में शीर्ष 5वां स्थान अर्जित किया है। बता दें कि आर्थिक विकास के कारण इस देश की बेरोजगारी दर 17 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक कम हो गई है।

आस्ट्रिया

26,177,413 के करीब जनसंख्या वाला देश आस्ट्रिया भी सुरक्षित देशों की गिनती में आता है। यहां पर भी अपराध दर काफी कम है। लेकिन यहां पर घूमने आने वाले टूरिस्टों और यहां पर रहने वाले स्थानीय निवासियों को जेबकतरों और पर्स-स्नैचर्स आदि घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप भी यहां पर घूमने आना चाहते हैं तो

आपको जेबकतरों से सावधान रहने की जरूरत होगी।

डेनमार्क

डेनमार्क 5,896,026 आबादी वाला देश है। बता दें कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार, यह दुनिया का 5वां सबसे सुरक्षित देश है। इस देश में अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और कम भ्रष्टाचार होने के साथ ही कुशल सुरक्षाबन मिलेगा। इसके अलावा यहां की हेल्थ सुविधाएं भी काफी बेहतर हैं। इस देश में लोग आरामदायक तरीके से अपनी जीवन व्यतीत करते हैं।

कनाडा

कनाडा की कुल आबादी 37,742,154 के करीब है। आबादी के लिहाज से कनाडा काफी छोटा देश है। यहां का अधिकतर हिस्सा बंजर जंगल है और यह बंजर जंगल हजारों मीलों तक फैला हुआ है। लेकिन घूमने के लिहाज से यह काफी सुरक्षित देश है। इस देश का अपराध दर भी काफी कम है।

सिंगापुर

सिंगापुर 59,43,546 के करीब आबादी वाला है। सिंगापुर में छोटी-मोटी चोरी और अन्य अपराधों के खिलाफ कुछ सख्त कानून हैं। जिसके कारण इसकी गिनती दुनिया के सुरक्षित देशों में होती है। हालांकि सिंगापुर को शहर-राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि यह दुनिया के दूसरे नंबर का सबसे सुरक्षित राज्य है।

जापान

जापान की जनसंख्या 125.93 मिलियन के आसपास है। सुरक्षा के लिहाज से यह सबसे सुरक्षित देश है। चीन और उत्तर कोरिया के करीब होने के बाद भी जापान एशियाई महाद्वीप का एक सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्थिर देश है। वैश्विक शांति सूचकांक में जापान हमेशा हाई स्कोर हासिल करता है।

चेक गणराज्य

चेक गणराज्य की आबादी 10,512,397 के करीब है। यहां पर हर वर्ष अपराध दर घटता प्रतीत होता है। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में चेक गणराज्य सुरक्षित देशों में से एक है। यहां पर आप सुरक्षा की परवाह किए बिना आराम से घूम-फिर सकते हैं।

स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड घूमने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट वहां पहुंचते हैं। बता दें कि यहां की आबादी 8.6 मिलियन के आसपास है। रहने और घूमने के लिहाज से यह देश सबसे ज्यादा बेस्ट है। फूड सिक्योरिटी के मामले में भी स्विट्जरलैंड दुनिया भर में चौथे स्थान पर है।

सिक्किम घूमने का बना रहे हैं प्लान तो...

इन खूबसूरत जगहों को करें एक्सप्लोर, जन्नत में आने का होगा एहसास

देश की टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन्स में नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों का नाम गिना जाता है। नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप प्लान करने वाले अधिकतर लोग सिक्किम घूमना नहीं भूलते हैं। वैसे तो सिकिम्म में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं। ऐसे में अगर आप भी सिक्किम घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को एक्सप्लोर करना न भूलें। इन खूबसूरत जगहों पर घूमने के बाद आपका वापस आने का दिल नहीं करेगा। हिमालय की गोद में बसा सिक्किम भले ही एक छोटा सा राज्य है। लेकिन यहां की खूबसूरत वादियों से लेकर नेचर की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको सिक्किम की कुछ शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में...

त्सोमगो झील की सैर

अगर आप सिक्किम में किसी रोमांटिक जगह पर घूमना चाहते हैं तो त्सोमगो लेक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। त्सोमगो लेक सिक्किम की राजधानी गंगटोक से महज 40 किलोमीटर दूर है। यह लेक 12,400 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इस लेक को चांगु झील के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि सर्दियों में यह लेक पूरी तरह से जम जाती है। वहीं बसंत ऋतु के मौके पर इस लेक की सुंदरता कई खूबसूरत फूलों से खिल उठती है।

जुलुक का दीदार

जुलुक का दीदार करने के लिए सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 3 घंटे का सफर तय करना होता है। इस दौरान रास्ते में 32 हेयरपिन मोड़ आपकी यात्रा को अधिक शानदार बना सकते हैं। वैसे तो जुलुक सिक्किम का एक छोटा सा और काफी खूबसूरत गांव है। लेकिन यहां से 11 फीट की ऊंचाई पर स्थित थुंबी व्यू प्वाइंट कंचनजंघा चोटी अपने खूबसूरत नजारों के लिए फेमस है। जुलुक की ट्रिप के दौरान कपुप लेक या हाथी झील का भी दीदार कर सकते हैं।

पेलिंग की ट्रिप

गंगटोक से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पेलिंग भी घूमने के लिए बेस्ट जगह है। यह जगह रोमांच के लिए फेमस है। पेलिंग का सफर एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट हो सकता है। यहां पर एडवेंचर के शौकीन लोग रॉक क्लाइंबिग, ट्रेकिंग, कयाकिंग, माउंटेन बाइकिंग, रिवर राफ्टिंग जैसी कई एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा सांगचोएलिंग मठ रिम्बी वॉटरफॉल स्काई वॉक और सेवारो रॉक गार्डन का दीदार कर अपने सफर को शानदार और रोमांचक बना सकते हैं।

रंवगला

रंवगला सिक्किम का खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय पर्वतों से घिरा रंवगला मैनम और तेंडोंग हिल्स टॉप पर मौजूद है। बता दें कि रंवगला गंगटोक से लगभग 63 किलोमीटर की दूर स्थित है। नेचर लवर्स के लिए रंवगला की सैर बेस्ट हो सकती है। यहां से आप ग्रेटर हिमालय के मनमोहक नजारों को बेहद नजदीक से देख सकते हैं।

इन टिप्स को फॉलो कर हॉलिडे को बनाएं शानदार, ऐसे करें पैसों की बचत

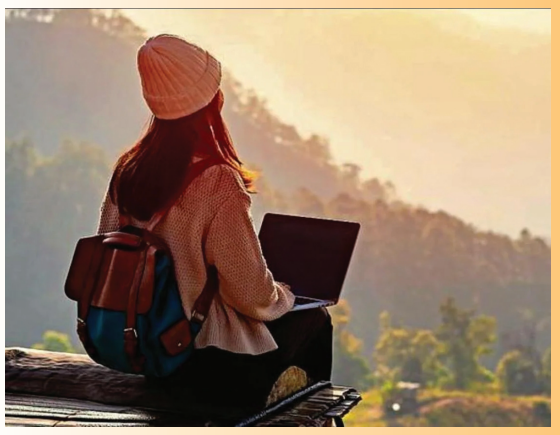

कई लोगों को घूमना काफी पसंद होता है। कई बार लगातार ट्रैवल करने के बाद भी छकान नहीं होती है। लेकिन घूमने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है। ऐसे में सेविंग्स का होना जरूरी होता है। घूमने के दौरान कई बार ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से घूमने की प्लानिंग करें तो आप पैसों की बचत कर सकते हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ट्रैवल के कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं। जिनकी मदद से आप ट्रैवल भी कर लेंगे और पैसों की सेविंग भी कर लेंगे।

हॉलिडे की योजना

अगर आप भी छुट्टी पर जाने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले यह डिसाइड करें की आप रिलैक्सिंग हॉलिडे के लिए समुद्र तट पर चाहते हैं या एडवेंचर्स करना चाहते हैं। जब आपको यह पता होता है कि आप घूमने के लिए कहां जाने वाले हैं तो वहां होने वाले खर्चे और यात्रा कार्यक्रम की योजना पहले से बना लें। इस दौरान आपके लिए रियलिस्टिक बजट बनाना आसान हो जाएगा।

रियलिस्टिक बजट

घूमने जाने की शुरूआत हॉलिडे रीयलिस्टिक बजट तय करने से शुरू होती है। आप कहीं भी घूमने जा रहे हों। कोई भी स्मार्ट ट्रैवलर यह बात काफी अच्छे से जानता है कि शानदार छुट्टियां बिताने के लिए एक रियलिस्टिक बजट की जरूरत होती है। जिसे आप आसानी से पहले ही बना सकते हैं।

ट्रैवल और खरीदारी

घूमने जाने के दौरान बुकिंग या खरीदारी पर कैशबैक कमा सकते हैं। इससे आपकी ट्रैवलिंग आसान हो जाती है। कई बार खरीददारी करने पर या बुकिंग करने के दौरान आपको कैशबैक मिलता है। इसलिए हमेशा इस ऑप्शन को ओपेन रखना चाहिए।

ऑफ सीजन में यात्रा

इस सीक्रेट को सभी स्मार्ट ट्रैवलर्स अपनाते हैं। अधिकतर ट्रैवल करने वाले ऑफ सीजन में यात्रा कर बड़ी बचत करते हैं। इस दौरान उनका ज्यादा खर्च नहीं होता है। क्योंकि वह ऑफ-पीक हॉलिडे सीजन में ट्रैवल करते हैं। ऑफ सीजन में ट्रैवल करने से फ्लाइट्स, होटल आदि सस्ते और आसानी से मिल जाते हैं।

फ्लाइट्स चुनते समय फ्लेक्सिबल

पर्यटकों की आवाजाही सप्ताह के कुछ दिनों में कम होती है। इस समय यात्रा करने पर आपको सस्ती उड़ान भरने का मौका मिल सकता है। फ्लाइट की कीमत के आधार पर आप अपनी छुट्टियों को प्लान कर सकते हैं। इससे भी आप अच्छी खासी सेविंग कर लेंगे।

हॉस्पिटैलिटी कंपनी

आपको बता दें कि अपने नियमित ग्राहकों के लिए कई प्रमुख होटल चेंस और एयरलाइंस बहुत कम या बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के लॉयल्टी प्रोग्राम्स पेश करती हैं। इस दौरान आपको होटल चेंस और एयरलाइंस के जरिए स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड

क्रेडिट या डेबिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। यह पॉइंट अर्जित करने का एक क्रिक और आसान तरीका है। जिसके बदले कई प्रमुख बैंक गिफ्ट्स और सर्विस के बदले में आपको रिवार्ड पॉइंट प्रदान करते हैं। जिन्हें किसी भी समय रिडीम किया जा सकता है।

सस्ता विकल्प खोजें

अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप उन विकल्पों को पता करें। जिनमें यात्रा सस्ती होने के साथ ही आने-जाने से लेकर रहने तक हर चीज के लिए काफी सारे विकल्प होते हैं। इस दौरान हॉलिडे प्लान करने के दौरान शानदार अनुभवों के लिए फ्लाइट्स के स्थान पर ट्रेनों की खोज करें।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

ईरान पर अमेरिका का बड़ा वार: 23 सितंबर से दुनियाभर में एयरलाइंस पर रोक, तेहरान ने दी हमले की चेतावनी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने ईरान के विमानन क्षेत्र के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई का एलान किया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी है कि 23 सितंबर से दुनिया भर में सभी ईरानी एयरलाइंस का संचालन पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। बेसेंट ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि ईरानी विमान लैंड करते हैं, तो कोई भी उन्हें ईंधन नहीं दे सकता, लैंडिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकता और न ही उनके टिकट बेच सकता है। जो भी देश, एयरपोर्ट या कंपनी ईरानी विमानों को किसी भी प्रकार की सहायता मुहैया कराएगी, उसे तत्काल डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली से पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी ओर, ईरान के केंद्रीय सैन्य कमान खतम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि उसने ईरान के खिलाफ कोई भी नई सैन्य कार्रवाई शुरू की तो पूरे पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर बेहद दर्दनाक हमले किए जाएंगे। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी इरना की ओर से जारी बयान में ईरान ने दावा किया कि अमेरिका क्षेत्रीय देशों के सहयोग से सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सेना ने कहा कि यदि अमेरिका ने कोई भी चूक की, तो बिना किसी विचार के जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ईरान की तरफ से यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उस धमकी के बाद आया है कि अगर ईरान ने अपना रुख नहीं बदला, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उधर, समुद्री निगरानी एजेंसी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने बताया कि होर्मुज में अज्ञात प्रक्षेपास्त्र से एक तेल टैंकर पर हमला किया गया है। हमले में चालक दल के दो सदस्य घायल हुए हैं।

ट्रंप और ममदानी की मुलाकात: मीडिया पर प्रतिबंध और बायकॉट के सवाल का भी दिया जवाब; क्या-क्या बोले?

अल्बानी, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मेयर पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की। इसी दौरान उनसे उन खबरों पर सवाल किया गया, जिनमें कहा गया था कि व्हाइट हाउस की ओर से कई मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में कुछ मीडिया संगठन ट्रंप की कवरेज का बहिष्कार कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मीडिया ने उन्हें बॉयकॉट करने की बात कही थी, लेकिन वास्तव में किसी ने उनका बॉयकॉट नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें मीडिया के बॉयकॉट की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रेस की भी एक जिम्मेदारी होती है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की और उनके कार्यकाल में कई बड़े काम हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आठ युद्धों को सुलझाया है और अमेरिका के आर्थिक आंकड़े देश के इतिहास में सबसे अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जो काम किए हैं, उन्हें मीडिया सकारात्मक तरीके से नहीं दिखाता। उनका कहना था कि उन्हें लगभग हमेशा नकारात्मक कवरेज मिलती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका में 21 ट्रिलियन डॉलर का निवेश आ रहा है, जो उनके मुताबिक अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन ने ऐसा किया है जो पहले कभी नहीं हुआ।

हूतियों के हमलों से सऊदी बेहाल: ब्रिटेन ने बढ़ाया मदद का हाथ; आरएएफ भरेगा लड़ाकू विमानों में ईंधन

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन ने यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बढ़ते हमलों के बीच सऊदी अरब को सीमित सैन्य मदद देने का फैसला किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने सोमवार को बताया कि रॉयल एयर फोर्स यानी आरएएफ सऊदी अरब के विमानों में हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा देगा। यह व्यवस्था कुछ हफ्तों के लिए होगी और हालात को देखते हुए इसकी समीक्षा की जाएगी। यमन में हूतियों और सऊदी समर्थित सरकार के बीच संघर्ष फिर तेज हो गया है। हूती विद्रोही सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। शनिवार को सऊदी राजधानी रियाद को निशाना बनाकर भी हमला किया गया था, जिसे बीच में ही रोक दिया गया। हूतियों ने लाल सागर और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में सऊदी शिपिंग के खिलाफ नाकाबंदी का एलान भी किया है। ब्रिटेन आरएफ के जरिए सऊदी विमानों को हवा में ईंधन भरने की सुविधा देगा। यह सहायता शुरुआती तौर पर कुछ हफ्तों के लिए होगी और इसकी समीक्षा की जाएगी। आरएएफ का एक वॉयजर विमान सऊदी विमानों को ईंधन देने के लिए इस्तेमाल होगा। ब्रिटिश अधिकारियों के मुताबिक विमान सऊदी के 'रक्षात्मक' अभियानों में मदद करेगा।

जयशंकर ने की पी4एम समिट की अध्यक्षता, कहा- वैश्विक व्यवस्था दबाव में, बहुपक्षीय सहयोग जरूरी

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के इतर बहुपक्षवाद शिखर सम्मेलन में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों पर जोर दिया। भारत ने सह-प्रायोजक के रूप में बहुपक्षवाद को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र में सुधार की वकालत की। सम्मेलन में वैश्विक चुनौतियों से निपटने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने इस पहल की सह-मेजबानी ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, ब्राजील, कनाडा, भारत और केन्या के साथ की। उन्होंने सभी महाद्वीपों से अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक व्यापक और विविध प्रतिनिधित्व पर प्रसन्नता व्यक्त की।

कोस्टा ने कहा कि हम सभी विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों और इतिहासों से आते हैं, फिर भी हम समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। विश्व इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां संघर्ष लगातार फैल रहा है। अंतरराष्ट्रीय कानून का बार-बार उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी शामिल हैं। बहुपक्षीय प्रणाली इस समय भारी तनाव में है। जलवायु परिवर्तन, महामारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आर्थिक असुरक्षा जैसी चुनौतियां इतनी व्यापक हैं कि कोई भी देश, चाहे

वह बड़ा हो या छोटा, उनका अकेले सामना नहीं कर सकता।

इसलिए हमें टकराव को सहयोग में बदलना चाहिए। उन्होंने बहुपक्षीय सहयोग, आपसी सम्मान और अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित एक वैश्विक नेटवर्क बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने इस पहल को शुरू करने के लिए राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, भारत सह-प्रायोजक के रूप में इस पहल में शामिल होकर प्रसन्न है। जयशंकर ने आगे कहा कि हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब वैश्विक व्यवस्था तनाव में है। पिछले कुछ दशकों से दुनिया में एक स्थिर पुनर्संतुलन देखा जा रहा है, जो एक लंबे समय से अपेक्षित संरचनात्मक विकास था। हालांकि, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, भू-राजनीतिक तनाव और वास्तविक संघर्षों ने इसे एक अलग चरित्र दिया है। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया, तो यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना पर ही सवाल उठाएगा। इसीलिए इस मोड़ पर बहुपक्षवाद का दृढ़ता से मुखर होना इतना आवश्यक है।

बहुपक्षवाद की आवश्यकता क्यों है : कोस्टा ने स्पष्ट किया कि बहुपक्षवाद के साझेदारों की यह पहल एक खुला मंच है। यह दुनिया के सभी हिस्सों के साझेदारों के लिए है जो सामान्य सिद्धांतों की रक्षा करने को तैयार हैं। इसका लक्ष्य ठोस समाधानों की दिशा में मिलकर काम करना है। यह मंच संवाद, गठबंधन निर्माण और व्यावहारिक सहयोग के लिए एक नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा। यह हमें सामान्य चुनौतियों का सामना करने में समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय प्रारूपों के कार्य का समर्थन करना है। हम साझा प्रतिबद्धताओं को ठोस कार्रवाई में बदलने में सहायता करेंगे। जयशंकर ने भी बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर दृढ़ता से जोर दिया। उन्होंने कहा कि यहां दांव पर केवल शब्द या अभिव्यक्तियां नहीं हैं। बल्कि बहुत वास्तविक मुद्दे हैं जिनका समाधान आवश्यक है। शांति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का भविष्य, जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय, उभरती प्रौद्योगिकियां और विकास वित्त, आतंकवाद का मुकाबला, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना, तथा आपदा लचीलापन सुनिश्चित करना और महामारियों की तैयारी करना। ये सभी सहयोग की इच्छा पर निर्भर करते हैं।

वैश्विक चुनौतियों से निपटने की प्राथमिकताएं क्या हैं : एंटोनियो कोस्टा ने इस संबंध में तीन मुख्य प्राथमिकताएं बताईं। पहली प्राथमिकता उन नियमों और संस्थाओं की रक्षा करना है जो हम सभी की सुरक्षा करते हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानून शामिल हैं। दूसरी प्राथमिकता जलवायु वित्त, सतत विकास, महामारी की तैयारी, आर्थिक लचीलापन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में प्रगति करना है। तीसरी प्राथमिकता हमारी संस्थाओं में सुधार करना है। उन्हें कल की दुनिया के लिए उपयुक्त बनाना है, न कि कल की दुनिया के लिए। कोस्टा ने भविष्य के लिए समझौता, संयुक्त राष्ट्र 80 पहल और अन्य सुधारों का उल्लेख किया। उन्होंने इन्हें संयुक्त राष्ट्र को अधिक सुसंगत, प्रभावी और कुशल बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। जयशंकर ने भी कहा कि हमने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, वह केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सबक यह है कि बेहतर के लिए प्रयास करते हुए अच्छे की रक्षा की जाए। यह उद्देश्य विभिन्न प्रकार के प्रयासों और पहलों के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

स्पेसएक्स को मिलेगी वाइल्डलाइफ की जमीन, कोर्ट ने खारिज की अंतरिम रोक की मांग; भड़के पर्यावरण समूह

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने टेक्सास में एक जमीन अदला-बदली (लैंड स्वैप) समझौते के तहत अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को 700 एकड़ से अधिक वन्यजीव अभयारण्य की जमीन सौंपने की ट्रंप प्रशासन की योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद पर्यावरण समूहों ने अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश फर्नांडो रोड्रिग्ज जूनियर ने सोमवार को पर्यावरण और आदिवासी समूहों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इस जमीन के हस्तांतरण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में नाकाम रहे कि इस सौदे से गल्फ कोस्ट क्षेत्र के पर्यावरण को कोई अतिरिक्त गंभीर खतरा पहुंचेगा, जो इलाका पहले से ही स्पेसएक्स के रॉकेट अभियानों के चलते काफी बदल चुका है।

यूएस फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस ने जून में स्पेसएक्स के साथ इस समझौते को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी थी। इस समझौते के तहत स्पेसएक्स अपनी 683 एकड़ निजी जमीन सरकार को सौंपेगा और इसके बदले में कंपनी को 'लोअर रियो ग्रांडे वैली नेशनल वाइल्डलाइफ रिफ्यूज' की 700 एकड़ से ज्यादा संघीय जमीन मिलेगी। यह वन्यजीव अभयारण्य टेक्सास सीमा पर चार काउंटियों में 1,03,000 एकड़ में फैला हुआ है। यह दुर्लभ वन्यजीवों का आवास और ऐतिहासिक धरोहर है। नक्शों से पता चलता है कि स्पेसएक्स को जो नई जमीन मिलने वाली है, वह अमेरिका-मेक्सिको सीमा के करीब कंपनी के मौजूदा रॉकेट लॉन्चपैड से बिल्कुल सटी हुई है।

पर्यावरण समूहों ने जताया कड़ा विरोध : मामले को लेकर सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के प्रवक्ता लाइकन जोर्डाहल ने कहा कि यह सौदा सार्वजनिक जमीन को स्पेसएक्स को तोहफे में देने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे अगले हफ्ते से ही इस वन्यजीव अभयारण्य पर बुलडोजर चलने का रास्ता साफ हो जाएगा और एक सार्वजनिक संपत्ति निजी फायदे में बदल जाएगी।

जोर्डाहल ने जोर देकर कहा कि अदालत का यह आदेश अंतिम फैसला नहीं है और उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह जमीन दक्षिण टेक्सास के लोगों और वन्यजीवों के लिए आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और वे इसे स्पेसएक्स से बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। स्थानीय लोग समुद्र तटों तक पहुंच बंद होने और रॉकेट विस्फोटों के खतरों को लेकर भी मस्क की कंपनी के बढ़ते विस्तार का विरोध करते रहे हैं।

पीठ में गोली धंसी रही, फिर भी आईसीई ने नहीं छोड़ा: अस्पताल से सीधे हिरासत में पहुंचा वेनेजुएलावासी

ऑस्टिन, एजेंसी। अमेरिका के टेक्सास में एक आईसीई अधिकारी की गोली से घायल 28 वर्षीय वेनेजुएलावासी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद फिर आईसीई हिरासत केंद्र भेज दिया गया। खास बात यह है कि उसकी पीठ में गोली अब भी फंसी हुई है। आव्रजन वकील केट लिंकन-गोल्डफिंच की प्रवक्ता फैबियाना मेलेंडेज रुइज के मुताबिक, विल्बर राफेल गार्सेस पेरेज रविवार को ऑस्टिन में डोरडैश की डिलीवरी कर रहा था। इसी दौरान ट्रैफिक रोकने के दौरान उसे गोली मार दी गई।

पेरेज को गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया था और उसकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई गई थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे दक्षिण टेक्सास आईसीई प्रोसेसिंग सेंटर, पियर्सल भेजा गया। पियर्सल ऑस्टिन से करीब 130 मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। वकील की प्रवक्ता के मुताबिक, उसकी पीठ में गोली अभी भी मौजूद है और उसे दर्द की दवा नहीं दी गई। पेरेज ने अपनी पत्नी को रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे फोन कर बताया था कि उसे गोली लगी है। उसकी पत्नी और वकील को रविवार शाम तक अस्पताल से उसकी स्थिति की जानकारी नहीं मिल सकी। ऑस्टिन के मेयर ने कहा है कि स्थानीय पुलिस को इस घटना की जांच में भूमिका मिलनी चाहिए।

वकील की प्रवक्ता के मुताबिक, पेरेज ने अपनी वकील से फोन पर बात की। उसने बताया कि पीठ में गोली फंसी होने के बावजूद उससे पूछताछ की जा रही थी। प्रवक्ता ने कहा कि पेरेज ने यह भी बताया कि उसे दर्द की कोई दवा नहीं दी गई। रविवार को गोली लगने के बाद उसकी पत्नी ने अस्पताल से उसकी हालत जानने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल ने शाम करीब छह बजे बताया कि उसे लगभग 90 मिनट पहले ही छुट्टी दे दी गई थी। आईसीई ने वकील को उसकी हिरासत की जानकारी नहीं दी, जिसके बाद कानूनी डेटाबेस और अन्य माध्यमों से पता चला कि उसे कहां रखा गया है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने कहा है कि वह एक ऐसे वेनेजुएलावासी की गोली लगने की घटना की जांच कर रहा है।

खुद को कमजोर मानने वाले दूसरे का चेहरा पढ़ने में ज्यादा माहिर; कैसे लोग संवेदनशील, सामाजिक दूरी क्यों?

लंदन, एजेंसी। जब कोई आपसे बात करते समय यह बोले कि वो बहुत बहादुर है, किसी से नहीं डरता या फलां काम तो बाएं हाथ का खेल है तो कई बार इस पर खीज उठना स्वाभाविक है। लेकिन आपने शायद ही कभी ऐसा महसूस किया होगा कि आपके चेहरे पर नाराजगी का भाव उभरने से पहले ही ऐसी डींगें भरने वाले चुप हो जाते हैं।

दरअसल, एक नए अध्ययन में पता चला है कि खुद को अंदर से कमजोर मानने वाले और लोगों के सामने बहादुरी का दावा करने वाले ज्यादा संवेदनशील होते हैं। सामने वाले के चेहरे पर गुस्से या घृणा का भाव वो तुरंत भांप जाते हैं। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन की तरफ से हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों के मन में अपने आत्म-सम्मान को लेकर अचेतन रूप से संदेह होता है, वो इस बात को बहुत

जल्द समझ जाते हैं कि सामने वाले को उसकी बात अच्छी लग रही है या नहीं। विज्ञान पत्रिका पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, सामाजिक रूप से नकारे जाने के प्रति संवेदनशीलता व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और दूसरों के साथ उसके सामाजिक संबंधों को भी गहराई से प्रभावित करती है। डॉ. कोर्जेनियोव्स्का ने बताया, जब किसी व्यक्ति का अचेतन आत्म-सम्मान कम होता है, तो उसका दिमाग संभावित सामाजिक अस्वीकृति से बचने के लिए लगातार अलर्ट मोड पर रहता है। शोध में सामने आया कि चेहरे पर घृणा के भावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील लोग नकारे जाने के डर से एक सामाजिक दूरी बना लेते हैं।

क्या है चेतन व अचेतन आत्म-सम्मान : शोधकर्ताओं के मुताबिक, आत्म-सम्मान केवल वह नहीं है जो हम ऊपर से महसूस करते हैं या दूसरों को बताते हैं। मनोविज्ञान इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटता है। स्पष्ट या चेतन आत्म-सम्मान वह भावना है जिसके बारे में हम सचेत होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति खुद को योग्य या प्रतिभाशाली मानता है और इसे शब्दों में बयां कर सकता है।

एजीआई हाउस या अय्याशी का अड्डा?: 37 पुलिस शिकायतों से उठे सवाल, टेक दिग्गजों की पार्टियों पर गंभीर आरोप

सैन फ्रांसिस्को, एजेंसी। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (एजीआई) के जरिये दुनिया बदलने का दावा करने वाले सिलिकॉन वैली के आलीशान टेक हाउस अपनी गतिविधियों को लेकर सवालों के घेरे में हैं। कैलिफोर्निया के बेहद महंगे इलाके हिल्सबोरो स्थित एजीआई हाउस में तकनीकी विशेषज्ञों, स्टार्टअप संस्थापकों और निवेशकों के जमावड़े के बीच होने वाली पार्टियों और वहां की घटनाओं पर पुलिस शिकायतों और अदालती दस्तावेज में गंभीर आरोप सामने आए हैं। 2022 से अब तक इस बंगले के संबंध में 37 पुलिस मामले और शिकायतें दर्ज हुई हैं। नेटवर्किंग के नाम पर आयोजित होने वाली इन

पार्टियों में न केवल नशीले पदार्थ व पार्टनर्स की अदला-बदली आम बात है, बल्कि दुष्कर्म, जबरन यौन संबंध बनाने और महिलाओं को बंधक बनाने के संगीन आरोप भी सामने आए हैं। 18,000 वर्गफुट के भूमध्यसागरीय शैली के इस बंगले में आठ कमरे हैं। एक कमरे का मासिक किराया 10 हजार डॉलर यानी करीब 9.5 लाख रुपये तक बताया गया है। सिलिकॉन वैली के शुरुआती हैकर हाउस छोटे-छोटे साझा मकानों में रहने और कोडिंग करने वाले युवा प्रोग्रामरों के लिए जाने जाते थे। एआई बूम के साथ स्वरूप बदला तो अय्याशी के अड्डे बनते चले गए।

बेलगाम पार्टियां, हवा में उड़ती कारें : एआई के पावर सेंटर एजीआई हाउस की नींव गूगल के पूर्व शोधकर्ता जेरेमी निक्सन ने रखी थी। इसमें ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी शीर्ष कंपनियों के इंजीनियर और स्टार्टअप फाउंडर्स रहते हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ऐसी ही एक अन्य हैकर-हाउस श्रृंखला द रेजिडेंसी के सलाहकार रहे हैं। गूगल के सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन यहां व्याख्यान दे चुके हैं, जबकि एलन मस्क की पूर्व पार्टनर और गायिका ग्राइम्स यहां परफॉर्म कर चुकी हैं। यहां एक पार्टी में बंगले के लॉन में हवा में स्टंट करती कार उड़ाई गई। मेहमानों को बग्घियों में बैठाकर नकली एफिल टॉवर तक लाया गया। पिछले साल दिसंबर में रात 2:22 बजे एक महिला ने पुलिस को फोन किया। महिला ने आरोप लगाया कि घर के एक निवासी ने उसे अंदर रोककर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। विरोध करने पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की। वह किसी तरह बंगले का ऊंचा गेट फांदकर बाहर निकल सकी। एजीआई हाउस से दो मील दूर टेक एन्फ्लुएंसर जिमी चेन ने 6 हजार वर्ग फुट का बंगला किराए पर ले रहा था।

महिलाओं के वेश में बच्चे के साथ घूम रहा था 16 हत्याओं का आरोपी 'मच्छर', पुलिस ने कैसे की गिरफ्तारी?

साओ पाउलो, एजेंसी। ब्राजीलियाई अधिकारियों के अनुसार, 16 लोगों की हत्या करने का आरोपी एक व्यक्ति पकड़े जाने से बचने के लिए जंगल में रहता था। उसे कमजोर शरीर-यष्टि के कारण स्थानीय लोग 'मच्छर' (मॉस्किटो) कहते थे। यह जानकारी उसे गिरफ्तार करने वाले ब्राजीलियाई पुलिस जांचकर्ता ने दी।

जांचकर्ता डगलस गार्सिया, जिन्होंने 33 वर्षीय जोरलान लोपेस दा सिल्वा की दो दिन तक चली खोज का नेतृत्व किया (जो 13 सितंबर को खत्म हुई)। उन्होंने सोमवार को 'द एसोसिएटेड प्रेस' को बताया कि संदिग्ध घनी झाड़ियों में अपने बनाए अस्थायी कैंपों में छिपकर रहता था। दा सिल्वा से जुड़ी हत्याएं पिछले तीन महीनों के दौरान ब्राजील के उत्तर-पूर्वी राज्य पाराईबा के दूर-दराज इलाके मुलुंगु में हुईं। गार्सिया ने कहा, 'इसी वजह से वह वर्षों तक पकड़े जाने से बचता रहा। जोरलान ज्यादातर जंगल में रहता था, इसलिए उसे ढूंढना और उन अपराधों से जोड़ना बहुत मुश्किल था जो शुरू में आपस में जुड़े हुए नहीं लग रहे थे।' गार्सिया ने बताया कि एक सार्वजनिक चौक पर 18 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या करने के बाद पुलिस को आखिरकार दा सिल्वा और अन्य अपराधों के बीच संबंध का पता चला। जांचकर्ता ने कहा कि सीरियल किलर का दावा है कि उसने केवल अपराधियों पर हमला किया है, लेकिन अब तक मिले सबूतों से पता चलता है कि ऐसा नहीं था। गार्सिया ने यह भी कहा कि दा सिल्वा ऐसे सबूत दे रहा है जिनसे पता चलता है कि उसने उन अपराधों से कहीं ज्यादा अपराध किए हैं जिनके लिए उस पर मुकदमा चल रहा है। हालांकि, उन्होंने आगे की जानकारी देने से इनकार कर दिया क्योंकि कुछ जांच अभी जारी हैं और कुछ मामलों को फिर से खोला जा रहा है। जांचकर्ता ने कहा कि पीड़ितों की पहचान और उनकी मौत से जुड़ी जानकारी गोपनीय रखी जा रही है ताकि अभियोजन पक्ष अपना काम कर सके। दा सिल्वा को सफेद धारियों वाली काली पोशाक, विग और नेल पॉलिश लगाए हुए पकड़ा गया।

अमेरिका: मीडिया संस्थानों से टकराव के बीच व्हाइट हाउस ने लॉन्च किया 'ट्रंप टीवी', क्या है पूरा मामला?

वाशिंगटन, एजेंसी। व्हाइट हाउस ने सोमवार को 'ट्रंप टीवी: द एसेंशियल्स स्टेशन' लॉन्च किया। यह 24/7 चलने वाला डिजिटल वीडियो स्ट्रीम है जिसमें प्रशासन की घोषणाएं, राष्ट्रपति के बयान और अन्य कंटेंट दिखाए जाएंगे। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ट्रंप प्रशासन को सीएनएन, एमएस नॉउ और पॉलिटिको की ओर से कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें व्हाइट हाउस से बाहर रखा गया था।

व्हाइट हाउस ने क्या बताया : व्हाइट हाउस ने कहा कि नई सर्विस प्रशासन के सबसे अहम पलों को एक जगह लाएगी। कंटेंट को रियल-टाइम में अपडेट किया जाएगा। इस स्ट्रीम को सोमवार शाम 7 बजे व्हाइट हाउस के यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया गया।

क्या है पूरा मामला : यह कदम सीएनएन, एमएस नॉउ और पॉलिटिको की ओर से ट्रंप प्रशासन के खिलाफ एक फेडरल मुकदमा दायर करने के कुछ घंटों बाद उठाया गया, जिसमें उन्होंने व्हाइट हाउस में अपनी पहुंच बहाल करने की मांग की थी। इन संगठनों का तर्क है कि प्रशासन का उनके पत्रकारों के क्रेडेंशियल रद्द करने का फैसला उनके 'फर्स्ट अमेंडमेंट' (संविधान के पहले संशोधन) अधिकारों का उल्लंघन है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या किया था : ट्रंप ने इन तीनों मीडिया आउटलेट्स की कवरेज की आलोचना करने के बाद उन्हें व्हाइट हाउस आने से रोक दिया था। इन संगठनों के अनुसार, शनिवार को उनके पत्रकारों को व्हाइट हाउस परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया और उनके प्रेस क्रेडेंशियल जब्त कर लिए गए।

सीएनएन के समर्थन में उतरे ये संस्थान : बता दें कि सीएनएन को उसके निर्धारित टेलीविजन पूल कार्यों से भी हटा दिया गया था। सीएनएन को एक निर्धारित असाइनमेंट से हटाए जाने के बाद, एबीसी, सीबीएस, फॉक्स न्यूज और एनबीसी भी व्हाइट हाउस टेलीविजन पूल में अपनी भागीदारी रोकने के मामले में सीएनएन के साथ हो गए। आम तौर पर, टेलीविजन पूल ब्रॉडकास्टर्स और दूसरे समाचार संगठनों को राष्ट्रपति से जुड़े कार्यक्रमों की साझा वीडियो कवरेज उपलब्ध कराता है। पूल के बाधित होने के कारण, व्हाइट हाउस की अपनी वीडियो फीड राष्ट्रपति के कार्यक्रमों के फुटेज का एक प्रमुख स्रोत बन गई है। सोमवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन तीन संगठनों की कड़ी आलोचना की, जिन्होंने उनके प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। 'जैसा कि उम्मीद थी, फेक न्यूज सीएनएन, एमएस नॉउ और पॉलिटिको ने व्हाइट हाउस और आपके राष्ट्रपति, यानी मुझ तक पहुंचने के लिए मुकदमा किया है। उन्हें अपने पक्ष में एक बढ़िया जज मिला है। वही व्यक्ति जिसने जिम अकोस्टा के पक्ष में फैसला सुनाया था, जो अब लगता है कि धरती से ही गायब हो गए हैं।

जज का नाम टिम केली है। दुख की बात है कि उन्हें ट्रंप ने ही नियुक्त किया था। दूसरे शब्दों में, बिना किसी सवाल के और हमेशा की तरह, हम अपील करेंगे क्योंकि फेक न्यूज वाले लोग और पब्लिकेशन जो सिर्फ नकारात्मक बातें लिखते हैं जो अनजान सूत्रों के हवाले से झूठी और बदनाम करने वाली कहानियां लिखकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन करते हैं। उन्हें दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑफिस तक पहुचने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। बहरहाल, मेरा फर्ज है कि मैं अपने देश की सफलता और सुरक्षा के लिए लड़ूं। फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं यह पक्का करने के लिए हर जरूरी कदम उठाऊंगा कि अमेरिका तरक्की करे।'

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

दिल्ली में जुटे देशभर के उलेमा, मस्जिद गिराने और धार्मिक आजादी के मुद्दे पर करेंगे मंथन

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की मौजूदा स्थिति, मस्जिद गिराने, संविधान के उल्लंघन और धार्मिक स्वतंत्रता पर मंडराते खतरों को देखते हुए जमीयत उलमा-ए-हिंद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक आपात बैठक बुलाई है। बुधवार को दिल्ली में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, देश के तमाम मौलाना और जमीयत से जुड़े हुए लोग शिरकत कर रहे हैं। बैठक के मुख्य एजेंडे में प्रशासन और न्यायपालिका के कुछ हालिया फैसलों और कदमों के संदर्भ में शरीयत के मामलों में बढ़ते हस्तक्षेप का मुद्दा प्रमुखता से शामिल है। इसके साथ ही देश में धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण, मस्जिदों के विध्वंस और इस्लामी मदरसों के सामने उत्पन्न चुनौतियों की समीक्षा की जाएगी। जमीयत उलमा-ए-हिंद ने साफ किया है कि संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, धार्मिक स्वतंत्रता और सभी नागरिकों के समान अधिकारों का संरक्षण ही देश की एकता और अखंडता की मूल बुनियाद है। संगठन के मुताबिक वर्तमान परिस्थितियां बहुत ही चिंताजनक हैं और इन पर गंभीर मंथन करना जरुरी है। कार्यकारिणी की इस बैठक में इन तमाम मुद्दों पर सामूहिक रूप से विचार-विमर्श के बाद आगे की रणनीति और ठोस कार्ययोजना के संबंध में बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

मणिपुर में 2.1 किलोग्राम 'याबा' टैबलेट जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

इंफाल (एजेंसी)। सुरक्षा बलों के एक संयुक्त अभियान में मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले से 2.1 किलोग्राम कृत्रिम मादक पदार्थ 'याबा' जब्त करने के साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि राज्य पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक संयुक्त टीम ने मंगलवार को मंत्रीपुखरी में बस के एक यात्री को रोका और 20,000 'याबा' गोलियां जब्त कीं जिनका कुल वजन करीब 2.1 किलोग्राम है। अधिकारी ने बताया कि थाई में 'याबा' का अर्थ 'उन्मादी प्रदान करने वाली दवा है। इसमें कैफीन और मेथामफेटामीन होता है, जो 'नियंत्रित पदार्थ अधिनियम' के तहत 'अनुसूची दो' का पदार्थ है। एक अन्य अभियान में राज्य पुलिस और असम राइफल्स की संयुक्त टीम ने काकचिंग जिले के वाइखोंग पुलिस थाने के अंतर्गत लमजाओ मयाई लीकाई इलाके से प्रतिबंधित 'पीपल्स लिबरेशन आर्मी' के एक सक्रिय सदस्य को पकड़ा है। अधिकारी ने बताया कि उसकी पहचान मैबम गुनामणि के तौर पर हुई है।

17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के बाद लेडी श्रीराम कॉलेज सहमा

-कॉलेज की प्रिंसिपल ने आनलाइन क्लासेस कीं शुरु

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजधानी दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास स्थित आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म की खौफनाक घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध किया है। इस दरिंदगी ने फिर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। दिल दहला देने वाली घटना के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन (एलएसआर) ने अपनी नियमित कक्षाएं रद्द की और बुधवार की सभी शैक्षणिक गतिविधियों को ऑनलाइन मोड पर स्थानांतरित कर दिया। उल्लेखनीय है कि लेडी श्रीराम कॉलेज घटना स्थल से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कॉलेज की प्रिंसिपल कनिका के. आहूजा ने बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलने के बाद ही उन्होंने कक्षाएं रद्द करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि उनके छात्रों की सुरक्षा और भलाई उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रिंसिपल ने अपने फैकल्टी मेंटर्स और कॉलेज काउंसलर को निर्देश दिया है कि वे किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर छात्रों की मदद के लिए उपलब्ध रहें।

चक्रवात अर्नब का पूर्वी तट पर भीषण खतरा : आंध्र, ओडिशा में हाई अलर्ट, स्कूल बंद

नई दिल्ली (एजेंसी)। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव अब शक्तिशाली चक्रवाती तूफान अर्नब में बदल गया है, जो भारत के पूर्वी तटीय इलाकों की ओर तेजी से आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि चक्रवात अर्नब के 23 सितंबर की शाम 5 बजे से 24 सितंबर की सुबह 5 बजे के बीच तट से टकराने की प्रबल आशंका है। संभावना है कि यह 23 सितंबर की आधी रात से पहले विशाखापत्तनम और गोपालपुर के बीच उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार करेगा। इस भीषण खतरे को देखकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और राष्ट्रीय व राज्य आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ/एसडीआरएफ) की टीमें तटीय क्षेत्रों में तैनात कर दी गई हैं। चक्रवात का असर केवल ओडिशा-आंध्र तट तक सीमित नहीं रहेगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तटीय ज़िलों में भी भारी बारिश और तेज़ हवाओं का अलर्ट जारी किया है, जहां 25 सितंबर तक खराब मौसम की चेतावनी दी गई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। बिहार में भी 23 से 28 सितंबर के बीच मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है, जिसमें कई इलाकों में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलेंगी।

विपक्ष ने कहा- एसआईआर पर चुनाव आयोग में भारी घमासान

आयोग ने कहा- सभी की सहमति से लिया फैसला, मतभेद नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी।
हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद चुनाव आयोग के भीतर फैसलों को लेकर चल रहे कथित मतभेदों को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एसआईआर प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा अन्य दो चुनाव आयुक्तों, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के बीच आंतरिक असहमति रही है। इस खुलासे के बाद राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि, चुनाव आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने इन सभी मतभेदों की खबरों का पूरी तरह से खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि आयोग के सभी फैसले आपसी सहमति और सर्वसम्मति से ही लिए गए हैं, जिसमें सभी सदस्यों की पूर्ण मंजूरी शामिल रही है।
सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आया था कि आयुक्तों ने नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने, चुनावी डेटा की सुरक्षा, आईटी सिस्टम और फॉर्म-6 में बदलाव जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं। पश्चिम बंगाल में लंबित अपीलों और सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्याओं पर भी सवाल उठाए जाने की बात कही गई थी। इन आंतरिक चर्चाओं और रिपोर्टों के आधार पर विपक्षी दलों ने आयोग को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस स्थिति को लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। उनका कहना है कि यदि संस्था के सदस्यों को निष्पक्ष रूप से काम करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो यह गंभीर विषय है। वहीं, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी मतदाता सूची के प्रबंधन और डिजिटल सिस्टम के केंद्रीय नियंत्रण को लेकर सवाल उठाए हैं, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में बहस और अधिक तेज हो गई है।
इन तमाम विवादों और चर्चाओं के बीच, चुनाव आयोग ने 2023 के कानून की धारा 18 का हवाला देते हुए अपने कामकाज की पारदर्शिता को रेखांकित किया है। आयोग का कहना है कि जहां तक संभव हो कार्य सर्वसम्मति से किया जाता है और बैठकों के दौरान अलग-अलग राय सामने आना तथा अंतिम निर्णय लिया जाना दो अलग बातें हैं। आयोग ने दोहराया है कि एसआईआर से जुड़े सभी निर्णय सभी सदस्यों की सहमति से ही तय किए गए हैं। एक तरफ जहां आधिकारिक सूत्रों ने किसी भी तरह के मतभेद से साफ इनकार किया है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न मुद्दों पर सामने आ रही आपत्तियों की चर्चाओं ने संस्था की कार्यशैली को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है, जिस पर राजनीतिक दलों की पैनी नजर बनी हुई है।

एसआईआर पर खुलासे से बवाल, प्रशांत भूषण बोले- ज्ञानेश कुमार को हटाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। हाल ही में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के भीतर ही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग के तीन सदस्यों के पैनल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी शामिल हैं। इनमें से दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले दस महीनों के दौरान कम से कम चौदह बार इस प्रक्रिया और नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम हटाने तथा बहाल करने जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। इस आंतरिक असहमति के सार्वजनिक होने के बाद से ही विपक्षी दलों के साथ-साथ कानूनी हलकों में भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इस खुलासे के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया के माध्यम से तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य सदस्यों के विरोध के बावजूद मनमाने और गैर-कानूनी तरीके से निर्देश जारी किए, जिसके कारण भारी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो गए हैं। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे गंभीर प्रकरण पर सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल पद से हटाते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह विवाद ऐसे समय में तूल पकड़ रहा है जब विभिन्न राज्यों में चुनावी सरगर्मियों के बीच एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई है कि बड़ी संख्या में जारी किए गए नोटिस मशीन जनित प्रतीत होते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह गहराता जा रहा है।

दिल्ली में धार्मिक टिप्पणी विवाद: अदालत ने पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली , एजेंसी।
दिल्ली की एक अदालत ने हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े एक गंभीर विवाद में दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। यह मामला एक छात्र-कार्यकर्ता और उनके पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग से जुड़ा है। भाजपा से जुड़ी अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने आरोप लगाया है कि इन दोनों ने सोशल मीडिया पर जानबूझकर ऐसा कंटेंट पोस्ट किया है, जिसमें हिंदू देवी-देवताओं के प्रति अपमानजनक और आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
दिल्ली की अदालत ने दिल्ली पुलिस को संवेदनशील मामले में अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा, यानी कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट) पेश करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता सचदेवा ने पहले दिल्ली पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उनका कहना था कि पुलिस की ओर से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। इसकारण उन्होंने न्याय के लिए अदालत का रुख किया और एफआईआर दर्ज करने की याचिका दाखिल की। मुख्य महानगर दंडाधिकारी (सीजेएम) मृदुल गुप्ता की अदालत में याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखक दिल्ली पुलिस को न केवल अपना जवाब दाखिल करने को कहा, बल्कि यह भी निर्देश दिया कि वह अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस की रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही यह अंतिम फैसला लिया जाएगा कि एफआईआर दर्ज की जाए या नहीं।

राम मंदिर दान चोरी केस में 7000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल

चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम शामिल नहीं

अयोध्या, एजेंसी।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर आठों आरोपियों के खिलाफ एंटी करप्शन कोर्ट में 7 हजार पन्नों से अधिक की विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। विवेचक बुधवार सुबह बड़े-बड़े बक्सों में चार्जशीट लेकर कोर्ट पहुंचे, जिसमें आरोप पत्र के साथ-साथ बैंक स्टेटमेंट और बैंक की जमा पर्चियां भी मौजूद थीं। इस चार्जशीट में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम न होने पर मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने गहरी नाराजगी और असंतोष जताया है।
दाखिल की गई इस चार्जशीट में कुल 173 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और इसमें 105 बार चोरी होने का जिक्र किया गया है। इसके अलावा, रिकॉर्ड की गई जांच में 803 चीजों का रिकॉर्ड पूरी तरह सही पाया गया है, जबकि 86 कीमती चीजों की रसीद नहीं मिल सकी है। पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से कार, गहने और 79.85 लाख रुपये नकद बरामदगी का भी चार्जशीट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को जानकारी दी थी कि एसआईटी इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करेगी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस. के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने मीडिया और सोशल मीडिया पर मूल्यवान चढ़ावे से संबंधित लगाए गए सभी आरोपों का गहन सत्यापन किया था। एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मंदिर के तीर्थयात्री सुविधा केंद्र के गिनती कक्ष के सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ कि गिनती प्रक्रिया में शामिल कुछ लोगों की मिलीभगत से कक्ष से नकदी को अनधिकृत रूप से निकालने या छिपाने के 105 मामले सामने आए थे।
चार्जशीट और एसआईटी की रिपोर्ट में कुल आठ आरोपियों की पहचान की गई है, तथा उनके बैंक खातों में जमा उस रकम का पूरा ब्यौरा दिया गया है जिसका कोई स्पष्ट स्रोत नहीं मिल सका है। इसके साथ ही, उन सभी चल और अचल संपत्तियों की जानकारी भी सार्वजनिक की गई है जिनमें चोरी का अवैध पैसा लगाया गया था। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और अधिवक्ताओं द्वारा नाम शामिल न किए जाने पर लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

जिसकी विरोधी रहीं सायोनी अब उसी भाजपा के लिए मांगेंगी वोट

बंगाल उपचुनावों में नए समीकरण बनते दिख रहे

कोलकाता, एजेंसी।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ सामने आया है, जहां अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखर आलोचक सायोनी घोष अब भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करती दिख सकती हैं। नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) ने नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भाजपा का समर्थन करने की घोषणा की है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अरूप रॉय की डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस ने भी इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे मुकाबला और भी त्रिकोणीय हो गया है। फिलहाल, एनसीपीआई ने अपने नेताओं के नामों का ऐलान नहीं किया है, जो भाजपा के लिए प्रचार करेंगे।
एनसीपीआई, जिसमें ममता बनर्जी से अलग हुए 20 बागी सांसद शामिल हैं, ने खुद को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) का दूसरा सबसे बड़ा भागीदार बताया है। पार्टी ने कहा है कि चूंकि उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए उन्होंने भाजपा के समर्थन में प्रचार करने का फैसला किया है। एनसीपीआई का दावा है कि एनडीए में वे भाजपा के बाद सबसे बड़े दल हैं। पार्टी अध्यक्ष ज्योति प्रकाश चटर्जी ने इस फैसले को राज्य के भविष्य से जोड़ा। उन्होंने कहा, एनसीपीआई एनडीए में भाजपा के बाद सबसे बड़ा साझेदार है। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राज्य के लिए काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लंबे समय से चली आ रही टकराव की स्थिति से अब राज्य के लोगों को छुटकारा मिलना चाहिए। अब टकराव का समय नहीं है, बल्कि साथ मिलकर काम करने का समय है। उन्होंने आने वाले समय में एक बड़ी बैठक की भी घोषणा की, जिसमें केंद्रीय और राज्य नेतृत्व के शामिल होने की बात कही गई। हालांकि, भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि इस समर्थन का मतलब किसी चुनावी गठबंधन से नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता सायंतन बसु ने कहा, यह अच्छी बात है कि एनसीपीआई ने भाजपा के लिए प्रचार करने का फैसला किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बंगाल में भाजपा और एनसीपीआई का कोई चुनावी गठबंधन हो सकता है या भविष्य में किसी भी तरह से सीटों का बंटवारा हो सकता है। दूसरी ओर, डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस ने इन उपचुनावों को ममता बनर्जी के खिलाफ सीधी लड़ाई माना है। पार्टी नेता संदीपन साहा ने कहा कि यह चुनाव साबित कर देगा कि असली तृणमूल वे ही हैं, क्योंकि ममता गुट की उम्मीदवार मुकाबले से पीछे हट गई हैं। इस बागी गुट ने नंदीग्राम से मोहम्मद एतेशामुल हक को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस भी राज्य में तृणमूल कांग्रेस में टूट का फायदा उठाने की कोशिश में है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि उनकी पार्टी को अब तृणमूल की जगह लेनी चाहिए और भाजपा विरोधी सभी मतदाताओं, खासकर अल्पसंख्यक मतदाताओं की स्वाभाविक पसंद के रूप में उभरना चाहिए।

लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा और राज्य का दर्जा दिलाने वांगचुक की पदयात्रा

कहा-हमने जब भी हक, संस्कृति संरक्षण की मांग की तो अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं

नई दिल्ली, एजेंसी।
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक बुधवार को लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को दोहराने के लिए 20 किमी की पदयात्रा करने वाले हैं। उन्होंने पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी थी। ये पदयात्रा लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा और राज्य का दर्जा दिलाने की मांग में की जा रही है। वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह कहते हैं इस महीने को शहीदों के महीने के रूप में मना रहे हैं। इसके लिए वह श्यामवैली में इकट्ठे हुए हैं। ये वही वैली है जो बटालिक के पास है, जिसमें कारगिल युद्ध में बहुत से जवानों ने जानें दी और लोगों ने बिना वर्दी के भारत की रक्षा की।
उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जब भी लोकतंत्र की मांग की पर्यावरण, हक और संस्कृति के संरक्षण की मांग की तो हम पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं! पिछले साल 24 सितंबर को गोलियां चलाई गईं जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी उन शहीदों को याद करते हुए हम एपेक्स बॉडी में हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। सरकार ने जो ज्यूडिशियल इंक्वायरी बैठाई है उसका जल्द से जल्द नतीजा आना चाहिए, साथ ही जो शहीद हुए हैं उन लोगों को सिर्फ 15-15 लाख के मुआवजे की बात कही गई है जो बहुत ही कम है और एक तरह का अपमान है।
हम सभी लोगों की सरकार से अपील है कि जैसे देश के सभी हिस्सों में हो रहा है वैसा ही हमारे लद्दाख के शहीदों को भी एक करोड़ का मुआवजा दिया जाए। वांगचुक ने ये पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- लद्दाख देश को बुला रहा है। लद्दाख के लोग हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं और अब समय आ गया है कि देश लद्दाख के साथ खड़ा हो। 23 सितंबर को लेह की ओर एक ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण पदयात्रा होगी। 24 सितंबर को एलबीए की ओर से उन 5 लोगों की याद में सर्व-धर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी, जिनकी पिछले साल अंधाधुंध गोलीबारी में मौत हो गई थी। हम आपके साथ और कई पत्रकारों व यूट्यूब के साथ पदयात्रा करने के लिए उत्सुक हैं। हमें उम्मीद है कि वे हमारा संदेश देश तक पहुंचाएंगे।

यूसीसी कोई कानूनी सुधार नहीं, विभाजन, व्यवधान और ध्यान भटकाने का हथियार

-कांग्रेस का आरोप- केंद्र सरकार ने विधि आयोग के निष्कर्षों को कर दिया नजरअंदाज

नई दिल्ली,, एजेंसी।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार और बीजेपी के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कोई कानूनी सुधार नहीं है, बल्कि ''विभाजन, व्यवधान और ध्यान भटकाने का एक हथियार'' और समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने का एक साधन है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए गठित राज्य सरकार की समिति से बंबई हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश के इस्तीफे और समिति के कामकाज को लेकर उठाए गए सवालों का हवाला देते हुए कहा कि इससे कई ''बड़े सवाल'' खड़े होते हैं। उन्होंने एक बयान में सवाल किया कि क्या संविधान सभा ने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना की थी, जिसमें हर राज्य अपनी अलग समान नागरिक संहिता बनाए? रमेश ने कहा कि इसका जवाब है बिल्कुल नहीं।''
रमेश ने इस बात का उल्लेख किया कि 17 जून 2016 को मोदी सरकार ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे को विस्तृत अध्ययन के लिए भारत के 21वें विधि आयोग के पास भेजा था। उन्होंने कहा कि व्यापक अध्ययन के बाद आयोग ने 31 अगस्त 2018 को 'पारिवारिक कानून में सुधार' पर अपना परामर्श पत्र जारी किया था। उन्होंने कहा कि परामर्श पत्र के पृष्ठ सात के अनुच्छेद 1.15 में आयोग का निष्कर्ष स्पष्ट था कि ''इस स्तर पर समान नागरिक संहिता बनाना न तो जरुरी है और न ही वांछनीय। रमेश ने कहा कि इसके बजाय विधि आयोग ने भारत की कानूनी और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखते हुए अलग-अलग पारिवारिक कानूनों में मौजूद भेदभाव को दूर करने की सिफारिश की थी।
कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उसी विधि आयोग के निष्कर्षों को नजरअंदाज कर दिया, जिसे उसने इस मुद्दे की जांच का जिम्मा सौंपा था। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में बीजेपी शासित कई राज्यों ने अपनी-अपनी समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। रमेश ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए के बाकी दलों की आवाज दबा दी गई है और बीजेपी उन्हें ''चुप करा रही है।'' कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के लिए समान नागरिक संहिता ''कोई ऐसा कानूनी सुधार नहीं है, जिसे पूरी तरह सोच-विचार के बाद, ज्यादा से ज्यादा व्यापक विचार-विमर्श और सार्वजनिक बहस के जरिए और अधिकतम संभव सहमति के साथ लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि असल में यह विभाजन, व्यवधान और ध्यान भटकाने का एक हथियार है, लोगों को परेशान करने और डराने का जरिया है, पूर्वाग्रहों को भड़काने और समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने का एक साधन है।